हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 मार्च, 1990

खण्ड 2 अंक 8

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 29 मार्च, 1990

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(8)1
अतारांकित प्र व एवम उत्तर	(8) 26
विभिन्न विशयो का उठाया गया	(8) 32
ध्याना कर्शणस प्रस्ताव	(8) 33

महेन्द्र गढ तथा रिवाडी जिलो मे भूमिगत जल स्तर नीचे जाने सम्बन्धी	
वक्तव्य	
सिचाई तथा बिजली राज्य मंत्री द्वारा प उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(8) 34
ध्याानाकर्शण प्रस्ताव	
पक्की ईटो की किमतो मे वृद्वि के कारण लोगो मे भारी रोश होने सम्बन्धी	(8) 37
वक्तव्य	
खाध तथा पूर्ति राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(8) 38
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(8) 40
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(8) 42
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(8) 42
समितियो की रिपोर्टस पे ा करना	
1. कमेटी औन सबौडिनेट लैजिसले ान की 21वी रिपोर्ट	(8) 43

2. कमेटी औन दी वैल्फेयर औफ भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज की 15 वी रिपोट	(8) 43
बिल्ज	
1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल अमैडमैड बिल 1990	(8) 43
2. दि हरियाणा अर्बन कट्रोल औफ रेट एण्ड ऐविक ान अमैडमैड बिल 1990	(8) 49
3. दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली अलाउसिंज एण्ड पैन ान औफ मैम्बर्ज अमैडमैड बिल 1990	(8) 52
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	
15.1.1990 तक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण को द ार्शाने वाले विवरण सम्बन्धी	8) 56

हरियाणा विधान सभा

वीरवार , 29 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1 चण्डीगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

ताराकित प्र न एवम उतर

श्री अध्यक्षः मैम्बर, साहेबान, अब सवाल होगे।

ताराकित प्र न सख्या 1073

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य, कामरेड हरपाल सिह, इस समय सदन मे उपस्थित नही थे।

Sainik School at Pali, Gothara

***1124. Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Chief Minister be pleases to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sainik School at Pati Gothara, District Rewari: and

(b) if so, the time by which the aforesaid school is likely to be opened ?

मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रका ा चौटालाः

(क) जी नही।

(ख) प्र न ही नही उठता।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि पाली गोठडा गांव मे सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए चीफ सैक्रेटरी, हरियाणा की तरफ से एक लैटर इ ू किया गया था जिसके तहत यह स्कूल वहा पर 1986 मे खुल जाना चाहिए था। गांव वालो ने इस स्कूल के खोले जाने के लिए फ्री औफ कौस्ट जमीन देने की औफर की थी। हमारे डिप्टी प्राईम मिनिस्टर ने भी 1 मई, 1989 को ऐलान किया था कि इस गांव मे सैनिक स्कूल खोला जायेगा। मै मुख्यमंत्री जी से जाना चाहूगा कि पाली गोठडा गांव मे किन कारणो से सैनिक स्कूल नही खोला जा रहा है ?

चौधरी औम प्रका ा चौटालाः स्पीकर साहब, रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रपोजल आई थी। इस प्रकार के स्कूल खोले जाने के लिए एक कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी के हिसाब से ही, पहली गवर्नमैंट के वक्त की प्रपोजल उस गांव मे सैनिक स्कूल खोलने की थी। उसके बाद चौधरी बंसी लाल की सरकार के समय मे पाली गांव मे सैनिक खोलने की प्रपोजल रिजैक्ट कर दी गई क्योकि उस समय की कमेटी की रिपोर्ट वहा पर स्कूल खोलने के बारे मे ठीक नही आई थी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, सैनिक स्कूल जो खोला जाना था, उसका दक्षिण हरियाणा मे खोले जाने का प्रावधान था। मै मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूगा कि वहा पर रेलवे स्टे ान की भी सुविधा है, रोड की भी सुविधा है और पानी भी उपलब्ध है। जब सारी सुविधाये अवेलेबल है तो फिर स्कूल वहा पर क्यो नही खोला जा रहा?

श्री अध्यक्षः सी0एम0 साहब यने बताया है कि आपकी ही सरकार ने वहा पर स्कूल खोलने की प्रपोजल बनाई थी और आपकी ही सरकार ने उस प्रपोजल को रिजैक्ट किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, कि पिछली सरकार ने ऐसी किसी प्रपोजल को रिजैक्ट किया था।

श्री अध्यक्षः गलत भाब्द को रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै इन्हे पुन बताना चाहूगा कि चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय मे पोली गांव मे सैनिक स्कूल खोलने की प्रपोजल थी लेकिन चौधरी बंसी लाल की सरकार ने उस प्रपोजल को रिजैक्ट कर दिया था।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि काग्रेस सरकार के समय मे ही वहा पर सैनिक स्कूल खोलने की योजना थी और काग्रेस सरकार के कार्यकाल मे ही इस प्रपोजल को रिजैक्ट कर दिया गया था। मै

इनसे जानना चाहूगा कि ऐसे स्कूल खोलने के लिए क्या मापदण्ड होने चाहिए ? दूसरे, मै यह बताना चाहूगा कि रिवाडी और महेन्द्रगढ जिले मे सारे हरियाणा से ज्यादा ऐक्स सर्विसमैन है और इस समय भी सबसे ज्यादा व्यक्ति इन्ही जिलो के फौज मे भर्ती है। इन्होने बताया है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वहा पर यह सैनिक स्कूल नही खोला जा रहा और बंसी की सरकार ही इस स्कीम को रिजैक्ट कर गई। मै मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूगा कि काग्रेस सरकार ने जो अच्छे काम किए है, क्या उन कामो को पूरा किया जायेगा। यानी काग्रेस सरकार की जो अच्छी पालिसी है उन पर भी ये अमल करेगे ?

Mr. Speaker: This is no supplementary. Please take your seat.

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ जिले मे सैनिको की तादाद को देखते हुए सैनिक सैक ान हुआ था। मै मुख्यमंत्री महोदय यह जानना चाहूगा कि क्या उनकी सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार को इस जिले मे सैनिक स्कूल खोले जाने का कोई प्रस्ताव रखा गया है ?

चौधरी औमप्रका ा चौटला: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से प्राफैसर साहब को बताना चाहता हू कि यह प्रपोजल केन्द्र सरकार की थी। इस स्कूल के लिए हरियाणा सरकार से जमीन और बिल्डिग मांगी गई थी। फिलहाल एक सैनिक स्कूल की प्रपोजल हरियाणा सरकार की तरफ से भेजी गई है। उसको मन्जूर

करना या न करना केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र मे आता है। केन्द्र सरकार की तरफ से जो तजवीज बनी है उस पर सरकार कमेटी के माध्यम से कार्य करेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि पाली मे जो सैनिक स्कूल खोलना था उसकी जब क्लीयरैस भी हो गई थी फिर भी वह स्कूल वहा पर क्यो नही खोला जा रहा है ?

चौधरी औम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदस्य महोदय की जानकारी के लिए यह बताना चाहूगा कि अभी तक स्कूल खोलने के लिए कोई सैक ान नही आई है। केन्द्र सरकार की प्रपोजल पर हरियाणा सरकार ने अपनी तयवीज भेजी है उसको मन्जूर करना या न करना रक्षा मन्त्रालय का काम है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि हरियाणा सरकार ने जो सैनिक स्कूल खोलने की तयवीज भजी है, उसके अलावा क्या नारनौल या महेन्द्रगढ मे भी ऐसा स्कूल खोलने के बारे मे केन्द्र सरकार को प्रपोजल भिजवाने की कृपा करेगे?

चौधरी औम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूगा कि हरियाणा सरकार के सामने किसी वि ोश जिले का सवाल नही है। सरकार

के लिए 16 के 16 जिले बराबर है और जिस जिले के लिए कोई बात उपयुक्त सोची जाएगी, उस पर ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय मै आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूगा कि सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए क्या माप दण्ड है ? यदि ये माप दण्ड पूरै हो तो क्या वहा पर सैनिक स्कूल खोला जाएगा ?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का जवाब तो उन्होने पहले ही दे दिया है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूछना चाहूगा कि जिस जिले के भूतपूर्व सैनिको की सख्या ज्यादा हो, क्या उस जिले मे सैनिक स्कूल खोले जाने मे कोई प्रायरिटी दी जाएगी ?

चौधरी औम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सैनिक स्कूल बनाने के लिए पुराने सैनिको की बात को ध्यान मे नही रखा जाता । मेरे विचार से नये सैनिक जहां से ज्यादा भर्ती हो वहां सैनिक स्कूलो खोलने के बारे मे विचार किया जा सकता है।

Constitution of a Committee for the Implementation of Reservation Policy

***1098. Shri Parma Nand:** Will the Chief Minster be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to constirure a Committee to ensure the implementation of reservation policy for the persons belonging to Scheduled Castes, Back ward Classes. ExServicemen and Handiscapped persons in the State and

(b) if so, the time bey which teh aforesaid Committee is likely to be constituted?

मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रका ा चौटालाः

(क) जी नही।

(ख) प्र न पैदा नही होता ।

श्री परमानन्दः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने 1987 मे चुनाव से पहले पिछले वर्गो के लिए 9 वायदे किय थे। वायदा नम्बर 37 पर एक कमेटी गठित करने का वायदा किया गया था। मै आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि क्या वे अपने पिता जी द्वारा किए गए वायदे को वापिस लेना चाहते है ?

मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से प्रोफैसर साहब को बताना चाहूगा कि जिस वक्त यह निणर्य लिया गया था, प्रोफैसर साहब उनकी वजारत मे वजीर थे, इसलिए उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी बनती थी। इस प्र ान का जवाब तो वे स्वय ही दे सकते है।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि क्या हरियाणा सरकार के प्रत्येक विभाग से रोस्टर प्रणाली लागू है और इसका उल्लघन करने वालो के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करने का प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर विचार करने के लिए हाउस की कमेटी बनी हुई है।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फरमाया कि जिस वक्त यह निर्णय लिखा गया, उस वक्त मै भी वजारत मे भाामिल था। अध्यक्ष महोदय, इस विशय पर कभी कोई निर्णय लिया ही नही गया यह जो केवल वायदा था। इस वायदे के मुताबिक जो निर्णय लेना था उसके बारे मे मैने दिनांक 4.7.1989 को तथा दिनांक 5.9.1989 को दो डी0ओ0 लैटर लिखे थे। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि क्या ये डी0ओ0 लैटर्ज उनके नोटिस मे है तथा इस कमेटी को बनाने के लिए क्या कोई कार्यवाही हुई है?

चौधरी ओमप्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसे कोई पत्र होगे तो उनके मुताबिक सदस्य महोदय को जवाब दे दिया जायेगा।

श्री दुर्गा दस्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, जो पद अनुसूचित और पिछडी जातियो के लिए और दूसरे लोगो के लिए आरक्षित है

उनको सुनि चत करने के लिए क्या कोई तरीका सरकार के पास है ? क्या पदों मे मुताबिक ठीक से भर्ती कर ली गई है?

चौधरी ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस मामले मे बाकयाद सविधान मे प्रोविजन है और एक कायदा तय है, उसके मुताबिक ही सिलैक ान और अप्वायमैट होती है।

श्री किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि आरक्षण की देख रेख के लिए इस हाउस की एक कमेटी बनी हुई है। क्या मुख्य मंत्री जी महोदय बतायेगे कि यह कमेटी जो भी रिकमैन्डे ान करेगी, वे सारी इम्पलीमैट की जायेगी ?

चौधरी ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस बात पर विचार किया जा सकता है।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या क्या प्रदे ा सरकार ने आरक्षण के बैकलीग को पूरा करने के लिए पिछले वर्श कोई अभियान चलाया था यदि चलाया था तो उस अभियान के अन्तर्गत कितने आरक्षित पदो को भरा गया है ?

Mr. Speaker: This question is not relevant.

श्री परमा नन्दः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूगा कि इसी हाउस के फलोर पर

आदरीणय होम मिनिस्टर ने बताया था कि 1150 सिपाही भर्ती किये गये थे लेकिन उसमें रिजर्वे ान पूरी नही थी। इस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि हरियाणा ऐग्रीकलचर मार्किटिग बोर्ड ने 260 आदमी भर्ती किये थे लेकिन इस मे भी रिजर्वे ान पूरी नही हुई थी। इसी प्रकार श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने सन 1988 के बजट सै ान मे बताया था कि फरीदाबाद कम्पलैक्स मे भाडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिंज मे बताया था कि सीटे पूरी नही हुई है। बिजली बोर्ड की रिपोर्ट भी यही है कि वहा पर भी सीटे पूरी नही हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की जो नीति है उसके मुताबिक अमल नही होता। इसलिए मै मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि उस नीति को सुनि ित बनाने के लिए क्या सरकार कोई फैसला करने या कोई और उपाय करने जा रही है ?

चौधरी ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदस्य महोदय को एक बताना चाहूगा कि इस प्रकार की कोई बात मत्री महोदय की तरफ से नही कही गई। यह तो एक कलियर फैसला है कि रिजर्वे ान सविधान के मुताबिक है और उसके मुताबिक ही सारी की सारी सीटे भरी जाती है। किसी वि ोश मामले को ले कर हो सकता है कि उस क्लास के कैडीडेटस पूरी दरखास्ते न दे पाये हो और उपयुक्त कैन्डीडेटस न मिल पाये हो। ऐसी परिस्थिति हो गई हो तो और बात है।

श्री किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, जहा कही भी भर्ती होती है, वहा भाडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के कैडीडेटस भी उपलब्ध होते है लेकिन इसके बाद भी रिप्रेजैन्टे ान पूरी नही दी जाती। इसलिए मै मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि उस बारे मे ये कार्यवाही करेगे ?

चौधरी ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कही नही होता। एकाध दफा यदि कही कैडीडेटस की कमी आ जाती है तो उसके लिए दुबारा प्रार्थना पत्र मांगे जाते है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, पिछले साल हमारे ऐक्स सर्विसमैन का बैकलोग था। क्या मुख्यमंत्री महोदय इस साल उस बैकलोग को इस पालिसी के तहत पूरा करेगे ?

चौधरी ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह सविधान की बात है और सदस्य महोदय तो खुद फौज मे रहे है। इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी सरकार रिजर्वे ान के मामले पूरी तरह है और उसके मुताबिक ही निर्णय लिए जाते है।

Opening of Training Centre at Mahendergarh under D.L.E.T Scheme

***1109 Shri Ram Bilash Sharma:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a traninig centre at Mahendergarh under the D.E.L.T Scheme; and

(b) if so, the time by which the centre is likely to be opened ?

ि ाक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुक्म सिंह):

(क) जी हा।

(ख) भारत सरकार से रा ि ा उपलब्ध होने पर इसे चालू किया जाएगा।

श्री राम बिला ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन मे भी यह बात आयी थी कि केन्द्रीय सरकार से इस उध्े ाय के लिए रा ि ा उपलब्ध होनी है। मै यह जानना चाहता हू कि रा ि ा उपलब्ध होने का जो प्रोसैस है, यह किस स्टेज पर है और यह रा ि ा कब तक उपलब्ध होने का अनुमान है?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर सर, डी0आई0ई0टी0 स्कीम का सारा ही पैसा भारत सरकार देती है। 29 लाख रूपया, जो बिल्डिग की कस्ट्रक ान के लिए टोटल खर्च का 50 प्रति त है, वह उन्होने अभी स्वीकार किया है। वह हमने 18.12.1989 को पी0डब्लू0डी0 के पास जमा करवा दिया है।

श्री कैला ा चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मै मत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि क्या ऐसे सैटर प्रदे ा मे और कही

पर भी खोले गये है और महेन्द्रगढ मे यह जो सैटर खोला जा रहा है इसमे स्टुडैटस की कितनी सख्या होगी ?

श्री हुक्त सिंहः स्पीकर साहब, दो सैटर सोनीपत और गुडगावं मे चल रहे है और 6 की भारत सरकार ने हमे और स्वीकृत दे दी है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, मै यह जानना चाहता हूं कि ये 6 सैन्टर्ज कहा कहा पर खोले जा रहे है? इसके अलावा एक बात मैने इनसे यह पूछी थी कि महेन्द्रगढ मे जो ट्रेनिग सैटर खोलते जा रहे है उसमे कितनी विधार्थी एक साथ पढ सकेगे ? यह पूछने का मेरा मतलब यह है कि वर्श मे कितने बच्चे वहा पर प्र ाक्षण प्राप्त कर सकेगे ?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, अम्बाला, महेन्द्रगढ, रोहतक, भिवानी, जींद और सिरसा मे ये 6 सैन्टर्ज खोले जा रहे है और इनमे सेग प्रत्येक मे 75 विधार्थियों को दाखिल किया जा रहा है।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि गुडगाव मे डाईट स्कीम के तहत जो ट्रेनिग सैटर खोला है, उसका भवन कब तक तैयार हो जायेगा? क्या उसके लिए भी रा ा पी0डब्लू0डी0 को दे दी गयी है ?

श्री हुक्म सिंहः जी हां, हमने उसकी रा ा पी0डब्लू0डी0 को दे दी ।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या ऐसा सैटर खोलने के लिए करनाल का भी नम्बर आयेगा ?

श्री हुक्म सिहः स्पीकर सर, हमने करनाल के बारे मे भी भारत सरकार को लिखा हुआ है।

श्री परमा नन्दः मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि जींद मे जो डाईट इस्टीच्यू ान खोलना है, क्या उसके लिए फडज पी0डब्लू0डी0 को दे दिये गये है ?

श्री हुक्म सिंहः जी हां। उसके लिए भी हमने 29 लाख रूपया 31.3.1989 को पी0डब्लू0डी0 के पास जमा करवा दिया है।

श्री दुर्गा दत्त अंत्रीः स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि केन्द्रीय सरकार से आज तक इस बारे मे हमे कितनी अमाउन्ट मिली है और अब तक कितनी अमाउन्ट यूटिलाईज हो चुकी है ?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर साहब 8 जिलो के लिए जो पैसा हमे मिलार है वह इस प्रकार है गुडगाव 28 लाख, सोनीपत 28 लाख, रोहतक 31.20 लाख, जींद 29 लाख, सिरसा 29 लाख, अम्बाला 31.20 लाख, भिवानी 29 लाख और महेन्द्रगढ 29 लाख। हमने यह पैसा पी0डब्लू0डी0 के पास जमा करवा दिया है।

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, हरियाणा स्टेट मे चार ऐसे जिले है जो अभी अभी बने है। क्या उन चार जिलो मे से यमुना नगर मे भी कोई ऐसा सैटर खोलने के लिए प्रपोजल भेजेगे ?

श्री हुक्म सिह: स्पीकर साहब, चार नये जिले हमारे बने है। हरियाणा सरकार को इसके खोलने के लिये 10 एकड भूमि देनी पडती है। हमने इनके जिला ि ाक्षा अधिकारियों को लिखा हुआ है कि वह भूमि का पता लगाकार और केस बनाकर भेजे। हम केस भारत सरकार को भेजेगे कि वह चार जिले भी इस स्कीम मे कवर किये जाये।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, अभी अभी मंत्री जी ने यह कहा है कि इन चार नये जिलो मे भी सैटर खोलने के लिए केस भारत सरकार को चला जायेगा। मेरा रादौर क्षेत्र नया नया यमुनानगर मे भाामिल हुआ है। क्या यह सैटर रादौर मे खोलने पर विचार करेगे ?

Mr. Speaker: How can it be said now? Please take your seat.

High Rates for selling eatable items at Bus Stands

***1114. Shri Atma Singh Gill:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the constractors of shops Bus stands on Chandigarh Delchi Highway charge exorbitant rates of eatable items from the passengers as compared to market rates; and

(b) if so, the action taken of proposed to be taken in this repsect ?

गृह मंत्री प्रो0 सम्पत सिंहः

(क) बस स्टैण्ड भााहबाद की दुकानो के ठेकेदारो के विरूद्ध कुछ ि ाकायते प्राप्त हुई है।

(ख) चण्डीगढ दिल्ली राय मार्ग पर भाहबाद बस अडडें की दुकानो को हरियाणा पर्यटन निगम को सौपने के सन्दर्भ मे मामला सरकार के विचारधीन है।

Incident of Beating Journalists

***1120. Shri Mangal Sein:** Will the Minister for Home & be pleased to state whether any incident of beating the Journalistsy Press Photographes andof snatching their Cames came to the notice of Government during the by election of Meham Assembly constituency; if so, the details thereof togetherwith the action taken in the matter?

गृह मंत्री प्रो0 सम्पत सिंहः मेहम विधान सभा चुनाव क्षेत्र मे हुए उप चुनाव के दौरान ऐसी किसी प्रकार की घटना की रिपोर्ट सरकार को नही की गई।

डा0 मंगल सैनः क्या गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि अखबार वालो के और प्रैस फोटोग्राफर्ज के कैमरे छीनने आदि की वारदात के बारे मे कोई खबर अखबारो मे छपी है या उन्होने कोई खबर पढी है ? अगर उन्होने ऐसी कोई खबर पढी है तो इस बारे मे क्या ऐक ान लिया गया है ?

गृह मंत्री प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अखबारो मे जरूर ऐसी बाते आई है लेकिन सरकार को किसी किस्म की कोई रिटन कम्पलेट किसी लैवल पर नही मिली है।

डा0 मंगल सैनः गृह क्या गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि अगर ऐसी कोई खबर अखबारो मे छपी है और महकमे के नोटिस मे आई है तो क्या सुओ मोटो उसको जुडीि ायल इक्वायरी के पास रैफरैन्स के लिए भेज देगे ?

प्रौ0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसके बारे मे प्र ान ही उत्पन्न नही होता।

श्री राम बिलास भार्माः क्या गृह मंत्री महोदय, बताने की कृप्या करेगे कि हरियाणा भवन दिल्ली मे पत्रकारो का एक दल मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होने इस बारे मे कोई ि ाकायत की थी अगर की थी तो इसकी इक्वायरी करवाएगे ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, पत्रकारो का एक दल जरूर मिला था और मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त उनसे कहा था कि आप लिखित रूप से ि ाकायत दे, हम ि ाकायत पर ऐक ान

लेगे, बाकयदा इक्वायरी करवाएगे और जो नुकसान हुआ है उसको कम्पन्सेट करेगे। मै सदन को बताना चाहूगा कि अभी तक उनसे उस बारे मे लिखित रूप मे कोई कम्पलेट नही आई है।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि अखबार मे छपी किसी बात का सरकार नोटिस लेती है ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, सरकार जरूर नोटिस लेती है लेकिन सब बातो का नोटिस नही लेती । अध्यक्ष महोदय, उन लोगो को आ वासन दिया था कि आप रिटन मे कम्पलेट दे, बाकयाद इक्वायरी करवाएगे, दोशी लोगो को सजा दी जाएगी तथा जो नुकसान हुआ है, उसका कम्पनसे ान देगे। लेकिन अध्यक्ष महेादय, अनफारचुनेटली रिटन मे हमारे पास कोई चीज नही आई है।

डा0 मगल सैनः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि पत्रकारो का जो ि ाश्टमण्डल मुख्य मंत्री जी से मिला था, उनकी क्या ि ाकायते थी ?

मुख्यमंत्री चौधरी औमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से डाक्टर साहब की जानकारी मे लाना चाहूगा कि उस ि ाश्टमण्डल के मिलने से पहले ही मैने यह फैसला कर लिया था और ब्यान भी दे दिया था कि जिस किसी अखबार के कौरेसपौन्डैन्टस के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है उसकी

इक्वायरी कराई जाएगी और अगर किसी का कैमरा यह अखबारो से सम्बन्धित किसी सामान का नुकसान हुआ होगा तो सरकार उसको कम्पनसेट करेगी, लेकिन यह बात तभी सम्भव होगी अगर सरकार के सामने कोई रिटन ि ाकायत आएगी। आज तक सरकार को कोई लिखित ि ाकायत नही मिली है।

श्री वीरेन्द्र सिहः अध्यक्ष महोदय, जब जुडीि ायल इक्वायरी का ऐलान किया गया था तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने प्रैस मे यह भी ब्यान दिया था कि वायलैस के इंसीडैस के अलावा पत्रकारो के साथ जो ज्यादती हुई अलैज की गई है, उसका रैफरेन्स भी हाई कोर्ट के जज को भेजगे। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उन्होने कोई ऐसा ब्याना दिया था ?

चौधरी औमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै सदन के माननीय सदस्य, जो इत्तफाक से ला ग्रेजुएट है, को यह बताना चाहूगा कि हरियाणा सरकार से 28 तारीख के सारें वाकयता की जुडीि ायल इक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के एक सिटिग जज को नियुक्त किया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि अगर 28 तारीख के वाकयता के साथ किसी अखबार वाले के साथ कोई ज्यादती हुई है तो क्या उसको भी इक्वायरी के लिए भेजने की कृपा करेगे ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जुडीि ायल इक्वायरी मे जो वायलैस मे डैथ हुई है, उन्ही वाकयात को भाामिल किया गया है।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य ला ग्रेजुएट है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या उनको माननीय सदस्य के ला ग्रेजुएट होने मे कोई सं ाय है ?

(इस प्र ान का कोई उतर नही दिया गया)

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, पत्रकारो का एक ि ाश्टमण्डल मुख्य मंत्री जी को हरियाणा भवन, दिल्ली मे मिला था। अध्यक्ष महोदय प्रैस थर्ड ऐस्टेट होता है और प्रजातन्त्र मे उसका बडा सम्मान है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि बडी सख्या मे जो पत्रकार मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होने जो ि ाकायते की थी, क्या उन पर वे गौर नही करेगे ?

प्रौ0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम बार बार रीपीट कर चुके है कि अगर प्रैस वालो के साथ कोई ज्यादती हुई है तो वे हमे रिटन मे दे। जब रिटन मे हमारे पास ि ाकायत आएगी तो हम बाकायदा कार्यवाही करेगे।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, इडिया टुडे मे आया है कि प्रैस वाले मेहम हत्याकाड से सम्बन्धित कैसेट सारे हरियाणा मे जगह जगह दिखा रहे है कि किस प्रकार से उनको

चुनाव के दौरान, मेहम के अन्दर मारा गया है और उनके कैमरा को छीना गया है। क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेगे कि अगर यह सब कुछ गलत है तो क्या सरकार उन कैसेटस को हरियाणा के अन्दर दिखाने पर बैन लगाने पर विचार रखती है ?

Mr. Speaker: This is no supplementary

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र के अन्दर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियो का जितना महत्व है उतना ही प्रैस का भी है। क्या यह अच्छा नही होगा कि सरकार द्वारा एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो प्रैस वालो के साथ बैठ कर आपसी तालमेल बनाये ताकि सरकार और प्रैस के दरमियान जो गल्तफहमियां या भ्रम पैदा हो गये है उनको दूर किया जा सके ?

प्रो0 सम्पत सिहः स्पीकर साहब, हमारी आपस मे कोई गल्तफहमी नही है। इस काम के लिए वाकायदा एक कमेटी बनी हुई है जो आपसी तालमेल बनाये रखती है। समय समय पर लोगो की, प्रैस वालो की सरकार से बातचीत होती रहती है लेकिन इस पर्टीकुलर बात के लिए किसी समिति का गठन करना उचित नही हैं। अगर हमारे पास उनकी तरफ से कोई रिटन कम्पलेन्ट आएगी तो हम अव य कार्यवाही करेगे।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से निवेनद करूगा कि अगर प्रैस वालों को इनसे कोई नाराजगी है असन्तोश है जिस के कारण वे वीडियो कैसट

जगह जगह दिखा रहे है और सरकार के बारे मे कह रहे है उस को काउटर करने के लिए सरकार को कोई न कोई प्रबन्ध अव य करना चाहिये ताकि प्रैस वालो मे सरकार के खिलाफ असन्तोश की जो भावना है नारजगी है उसको दूर किया जा सकते।

प्रों0 सम्पतं सिंहः स्पीकर साहब, काउटर करने की कोई बात ही नही है। सरकार से किसी को कोई नारजगी नही है।

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेहन के अन्दर 28 तारीख को जो हत्याए हुई है, उस बारे मे तो सरकार ने जुडीि ायल इक्वायरी के आदे ा दे दिये है लेकिन वायलैन्स से सम्बन्धित बातो को उस इक्वायरी मे कोई जिकर नही किया गया है। आम जनता के साथ और अखबार वालो के साथ जो ज्यादतिया हुई है, क्या सरकार उनके बारे मे भी जांच करवाने का विचार रखती है ?

प्रों0 सम्पतं सिंहः अध्यक्ष महोदय, वायलैन्स के कारण जो डैथस हुई है उन्ही केसिज के बारे मे जुडीि ायल इक्वायरी के आदे ा दिये गये है।

श्री किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, बार बार सरकार की और से यह कहा जा रहा है कि उनके पास कोई लिखित ि ाकायत नही आई है मै आपके माध्यम से उन से यह जानना

चाहता हू कि क्या यह जरूरी है कि सरकार के पास लिखित कम्पलेन्ट आये, तभी सरकार कार्यवाही करेगी ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है कि कोई ि ाकायत सरकार के पास आये तभी उस पर इक्वायरी हो सकती है। जितने ये जनता के हामी है हम इनसे ज्यादा जनता के और प्रैस वालो के हामी है।

श्री दुर्गादत्य अत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार की और से यह कहा गया कि प्रैस का एक प्रतिनिधि मडल मुख्यमंत्री महोदय से मिला था। उस वक्त जो प्रैस वालो के साथ इनकी बातचीत हुई थी, क्या उस बातचीत के उनको पूर्ण रूप से तसल्ली ही गयी है ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, बाकायदा उनको पूरी तसल्ली हो गयी है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः अध्यक्ष महोदय, पिछले एक महीने से समाचार पत्र बराबर यह खबरे छाप रहे है कि प्रैस वालो को मेहम के अन्दर बुरी तरह से पीटा गया और उनके कैमरे बगैरह छीन लिये गये । मै आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही करने के लिये इस तरह रकी ऐवीडैनसिज उपयुक्त नही है ? क्या इस तरह के सबूतो के आधार पर सरकार कार्यवाही करने के लिए तैयार है ताकि प्रैस वालो को

या दूसरे लोगो को जिनके साथ ज्यादती हुई है, कोई तसल्ली हो सके ? क्या उनका भ्रम दूर करने की सरकार कोि ा ा करेगी ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जब हम बार बार कर रहे है कि लिखित रूप मे दो तो प्रैस वाले सामन क्यो नही आ रहे है ? हम तो अपने माननीय सदस्यो को भी यह कहेगे कि अगर प्रैस वालो के साथ कोई ज्यादती हुई है तो वे हमे लिखित रूप मे दे, हम कार्यवाही करेगे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिहः अध्यक्ष महोदय, मेहम मे जो कांड हुआ है उसके कारण से आम जनता मे और अखबारो वालो के मन मे एक भ्राम की स्थिति पैदा हो गयी है। इसलिये मेरी आपके माध्यम से सरकार से एक प्रार्थना है कि अगर इन सभी बातो की छानबीन के लिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए तो लोगो का भ्रम दूर हो जाएगा और जो लाछन सरकार के ऊपर लगा हुआ है, वह भी हट जाएगा। क्या सरकार इन सभी बातो के लिए हाउस की एक कमेटी बनाने पर विचार करेगी ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, सरकार पर कोई लाछन वाली बात नही है न ही कोई किसी के मन मे भ्रम है। इसका जीता जागाता सबूत जीन्द की रैली है, जिसमे 10 लाख के करीब लोगो भाामिल हुए। जनता इस सरकार से खु ा है। ये काग्रेसी भाई तो पिछड चुके है, जनता ने इनको मार गिराया है

जिसके कारण इनके मन मे काफी दर्द है जिसको ये लोग अभी तक निकाल नही पाए।

10.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि अगर इनके सामाने विडियो पे ा कर दिए जाए तो लिखित रूप मे दिया जाए तो कोई ऐक ान लेगे ?

प्रो0 सम्पत सिहः हमारे सामने कोई भी बात लिखित मे आती है तो उस पर ऐक ान लेते है।

श्री परमा नन्दः अध्यक्षम महोदय, प्रैस का एक ि ाश्टमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला था। उसने इनके सामने जुबानी ि ाकायत की थी। क्या इस प्रकार आमने सामने की ि ाकायत पर सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

चौधरी औमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस प्र ान को भाायद ज्यादातर सदस्य बार बार इसलिए कर रहे होगे ताकि उनके नाम अखबार मे आ जाए। मैने पहले ही बहुत स्पश्ट कर दिया है और मै फिर आपके माध्यम से इस बात को और स्पश्ट करना चाहूगा कि जो प्रतिनिधिमडल मुझे मिला था, मैने उनको बाकायदगी से यह कहा था कि अगर आपकी कोई ि ाकायत हो तो सरकार के पास लिख कर भेजे, हम इन्कवायरी

करवाएगे। उनकी तरफ से ऐसी कोई ि ाकायत नही आई है इसलिए बार बार ऐसी बात कहने की कोई तुक नही है।

तारकित प्र ान सख्या 1127

यह प्र ान पूछा नही गया क्योकि माननीय सदस्य, श्री भगवान सहाय रावत, इस समय सदन मे उपस्थित नही थे।

पूछा नही गया क्योकि माननीय सदस्य, श्री भगवान सहाय रावत, इस समय सदन मे उपस्थित नही थे।

Part Payment of Electricity Bills

***1108 Shri Harman Singh:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of tubewells disconnected upto March, 1990 on account of non payment of Electricity Bill in teh State: and

(b) whether the Government will consider thye request to restore the tubewells connections of those farmers who will make the part payment of their Electricity Bills ?

सिचाई तथा बिजली राज्य मंत्री श्री सचदेव त्यागी:

(क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 31.1. 1990 तक बिजली के बिलो की अदागयी न करने से कनैक ान काटे गए नलकूपो की सख्या 6251 है।

(ख) कनैक ान कटने की तिथि से तीन वर्श के भीतर निवेदन प्राप्त होने पर आि ाक अदायगी करने से निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार ऐसे केसो मे कनैक ान बहाल किए जा रहे है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, अब गेहू पक रहा है इसलिए जिनके बिलो की रकम बकाया है क्या उनके कनैक ान फसल कटने तक काटने से रोक जाएगे ?

श्री सचदेव त्यागीः ऐसा कुछ नही है। प्रैसकाइब्ड प्रोसीजर के हिसाब से री कनैक ान किए जाते है।

श्री अध्यक्षः सवाल यह है कि अब गेहू पक रही है और जो डिफाल्टर है उनके कनैक ान गेहू कटने तक न काटे जाए।

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, जो डिफालटर है जिनकी तरफ से बकाया है उसके लिए एक तरीकार है। पहले तो टैम्पोरेरी कनैक ान काटा जाता है अगर सात दिन के अन्दर पेमैट जमा न करवाई जाए तो कनैक ान काट दिया जाता है। उसके बाद 50 रूपए जमा करवाने के बाद कनैक ान दोबारा जोड दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः त्यागी साहब, सवाल यह है कि एक आदमी ने आपका पैसा देना है, उसका कनैक ान अभी कटा नही है और न ही उसको कोई काटने का नोटिस दिया हुआ है तथा न ही काटने गया है। क्या गेहू कटने तक उनका कनैक ान नही कटेगा ?

श्री सचदेव त्यागी: ऐसे केस मे वह पार्ट पेमैट कर दे।

सेठ लक्ष्मन दास बजाज: स्पीकर साहब, करनाल भाहर मे जिन लोगो ने पांच वाट के कनैक ान मजूर करवाए हुए है उनको सात वाट के कनैक ान के हिसाब से लाखो रूपए के बिल के नोटिस जारी किए गए है। मै यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार, जो दो वाट का फालतू बिल आया है उसको ठीक करने की कृपा करेगी ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, मेन सवाल चूकि टयूबवैल्ज के कनैक ाज के बारे मे है इसलिए इस सप्लीमैटरी का इससे कोई संबध नही है।

श्री कैला ा चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जिला महेन्द्रगढ मे कुओ के पानी का लैबल चूकि बहुत नीचे चला गया है इसलिए उनका उपायोग भी बंद कर दिया गया है। मै आपके माध्यम मे मंत्री जी से जानता चाहता हू कि अगर वहां का किसान अपने किसी दूसरे खेत मे रिंग म ाीन की सहायता से कुआ खोद लेता है तो क्या उसको वही कनैक ान उस जगह पर दे दिया जाएगा यानी उसका पहले वाला टयूबैल्ज का कनैक ान दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, उसके लिए नया कनैक ान लेना पडेगा।

श्री हरमना सिंहः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि बिजली बोर्ड किसानो से टयूबवैल्ज के री कनैक ान के वक्त कौस्ट आफ मैटीरियल मागता है क्या उसको खत्म किया जाएगा क्योकि री कनैक ान तो री कनैक ान ही है कोई नया कनैक ान नही है ?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, यदि कोई किसान डयू डेट के 7 दिन तक बिजली का बिल जमा न करवा तो उसका कनैक ान टैम्पोरेरी तौर पर काट दिया जाता है और अगर वह बिल के साथ 50 रूपए ऐक्सट्रा जमा करवा देता है तो उस कनैक ान को दोबारा जोड दिया जाता है। अगर कोई किसान डयू डेट के 30 दिन तक बिल जमा नही करवाता है तो बिजली का कनैक ान परमानैटली काट दिया जाता है जिस किसान के टयूबवैल का कनैक ान परमानैटली डिस कनैक्ट किया जाता है उसको रीकनैक्ट करने का प्रोसीजर यह है कि तीन गुणा सिक्योरिटी, टोटल बिल का वन थर्ड भोयर और बाकी बिल को दो किस्तो मे जमा करवाने का अडरटेकिग दे तो उसको दोबारा कनैक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई किसान 30 दिन के बाद और आगे तीन साल तक बिजली का बिल जमा नही करवाता है तो उसको दोबारा कनैक ान देने का यह प्रोसीजर है कि उसको तीन गुणा सिक्योरिटी, कौस्ट आफ केबल, कौस्ट आफ इरैक ान और डिसमैटल चार्जिज लिए जाते है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मै आपमे माध्यम से मत्री से यह जानना चाहता हू कि क्या किसानो से केबल का खर्चा लेना बंद करने के बारे मे कोई विचार किया जाएगा ?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, अभी ऐसा कोई विचार नही है।

श्री सरबूल सिंहः स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड की तरफ से किसानों को चार चार पांच पाच महीने तक बिजली का बिल नही भेजा जाता। अब बिजली बोर्ड वालो को यह मालूम हो गया है कि किसान लोग फसे हुए है। इसलिए उनको बिल भेज दिए है, जिसके कारण किसान लोग बढे परे ाान है। यदि अग वे बिल जमा नही करवाएगी तो उनके कनैक ान काट दिए जाएगे। मै यह जानना चाहता हू कि क्या उन किसानो को ऐसी कोई रियासत दी जाएगी जिनको चार चार पांच पाच महीने तक पहले तो बिल नही भेजे और अब बिल भेज दिए है। अब अगर वे जमा न करवा सके तो उनके कनैक ान न काटे जाए ?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, यदि इस बारे मे लिख कर ि ाकायत की जाएगी तेा उस पर गौर कर लिया जाएगा।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 6251 टयूबवैल्ज के कनैक ान काटे गए है उनकी तरफ कितना पैसा बकाया है ?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, उनकी तरफ 156 लाख रूपए बकाया है।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस साल अब तक कितने नए कनैक ान दिए गए ?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, इस साल जनवरी 1990 तक 1202816 डोमैस्टिक कनैक ाज, 11000079 कोमि र्यल कनैक ांज, 3803 इडस्ट्रियल कनैक ाज और 14384 टयूबवैल कनैक ाज दिए जा चुके है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो 14384 कनैक ांज टयूबवैल्ज को दिए गए बताए है इसमे से महेन्द्रगढ जिले मे कितने टयूबवैल्ज को कनैक ाज दिए गए कितने किसानो की ऐप्लीके ांज कनैक ान के लिए पेडिग है ?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, इस समय डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्फर्मे ान मेरे पास उपलब्ध नही है। अगर माननीय सदस्य इस बारे मे सैपरेट नोटिस देगे तो बता दिया जाएगा।

Construction of Over Bridge on Delhi Rewari Railway Line

***1122. Capt Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an over beidge on Delhi Rawari Railway line at the following roads:

(i) Rewari Jhajjar

(ii Rweari Narnaul ;

(b) if so, the time by which the above said bridges are likely to be constructed;

(c) whether there is alos any proposal under consideration on of the Government to consturct by pass connecting Narnaul Rohtak Raod with the Delhi Raod: and

(d) if the reply to part (c) in the affirmative the time by which the said by pass is likely to be constructed?

लोक निमार्ण मंत्री श्री औम प्रका ा भारद्वाजः

(क) जी हां

जी नही।

(ख) वित्तीय स्थिति जटिल होने के कारण रिवाडी झज्जर सडक पर ऊपरि पुल के लिये कोई समय निर्धारित नही किया जा सकता ।

(ग) जी नही।

(घ) प्र न उत्पन्न नही होता।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम मे मंत्री जी से जानना चाहूगा कि रिवाडी झज्जर और रिवाडी नारनौल रेलवे लाईन पर ऊपरी पुल बनावे जाने की कब सैक ान हुई थी और इस पर कितनी लागत आनी थी ? मै इनकी जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूं कि वहा पर ट्रेंफिक हैवी होने के कारण दुर्घटनाए भी बहुत ज्यादा हो रही है। मै जानना चाहूगा कि हैवी ट्रेफिक ध्यान मे रखते हुए क्या मंत्री महोदय कोई आ वासन देगे कि इतने समय इन पुलो को बना दिया जायेगा?

श्री औमप्रका ा भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, इसकी स्टेट की तरफ से ऐप्रुवल अगस्त 1986 मे हुई थी और इस पर कुल लागत 2 करोड 3 लाख 96 हजार रूपये आएगी।

कैप्टन अजय सिह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरे सवालों का जवाब मंत्री जी ने नही दिया है। मै इनसे पुन जानना चाहूगा कि इन पूलो के बनाये जाने मे देरी क्यो हो रही है। दूसरे इन्होने अपने लिखित उत्तर मे कहा है कि रिवाडी के अन्दर बाई पास नही बनाया जायेगा। मै इन्हे पुन बताना चाहूगा कि रिवाडी नया जिला बन गया है और वहा पर ट्रैफिक भी बहुत अधिक बढ गई है जिस कारण आये दिन दुर्घटनाए बढती जा रही है। मै इनसे जानना चाहता हू कि हैवी ट्रफिक को ध्यान मे रखते हुए वहां पर यह रोड बनाया जाना क्यो पौसीबल नही है ?

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः स्पीकर साहब, इन्होने कई सवाल इक्टठे ही कर दिए है। कभी तो ये बाई पास की बात करते है तो कभी ऊपरि पुल की बात करते है।

मुख्यमंत्री चौधरी औमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदस्य साथी को बताना चाहूगा कि कोई नया जिल बना जाने से ही एकदम हैवी ट्रेफिक या दुर्घटनाए नही बढ जाती। नए जिले इसलिए बनाये जाते है ताकि लोगो को सुविधा अधिक से अधिक मिल से। जो बात मै अब बताना चाहता हू कि वह हालाकि इस सवाल से संबध तो नही रखती, फिर भी मै सदस्यो की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार को ने ानल हाई वे न0 8 व 10 को मिलाने के लिए लिखा है।

कैप्टन अजय सिह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पुन जानना चाहता हू कि जब यह स्पीकृति 1986 मे मिल गई थी इसको बनाये जाने मे अब देरी क्यो है?

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऊपरि पुल बनाये जाने का सवाल है, इस बारे मे मै इन्हे बताना चाहूगा कि ऐसे पुलो के लिए 50 परसैन्ट पैस हरियाणा सरकार की तरफ से और 50 परसैन्ट पैसा रेलवे की तरफ से दिया जाता होता है। इन पुलो के बनाये जाने के लिए हमने रेलवे वाले के

साथ अब तक 18 लैटर्ज का आदान प्रदान किया है। जब रेलवे वाले अपना पैसा सैक ान कर देगे तो काम भाुरू कर देगे। हमारी तरफ से कोई देरी नही है और न ही कोई कमी है।

श्री कैला ा चन्दः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय की जानकारी मे कि रिवाडी नारनौल रोड राजस्थान तक जाता है और यह खेतडीबास और सोकर तक भी जाता है। क्या ये इस बात को ध्यान मे रखते हुए इस पुल बनाये जाने की आव यकता महसूस नही करते ?

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः स्पीकर साहब, इनका सवाल इस सवाल के तो संबधित है ही नही।

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, आप दुबारा सवाल पूछे।

श्री कैला ा चन्द भार्माः अध्यक्ष महोदय, इन्होने अपने जवाब मे कहा है कि रिवाडी नारनौल रेलवे लाईन पर ऊपरि पुल बनाना विचाराधीन नही है। क्या इनकी जानकारी मे यह बात है कि रिवाडी नारनौल रोड राजस्थान तक जाता है और इस मार्ग पर खेतडीबास और सीकर का इलाका भी पडता है जिस कारण इस रोड पर हैवी ट्रफिक है ? क्या इन हैवी ट्रफिक को ध्यान मे रखते हुए इस पुल को बनाये जाने के लिए सरकार दुबारा विचार करेगी ?

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले ही जवाब दिया है कि फिलहाल कोई प्रपोजल नही है।

श्री सीताराम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मत्री महोदय, ने अपने जवाब बताया है कि जब से इसकी स्वीकृति मिली है तब से लेकर अब तक इस सबंध मे 18 लैटर्ज रेलवे विभाग को लिखे गए है। इन द्वारा 18 पत्र लिखे जाने के बाद भी मामला ज्यों का त्यों है। क्या इतने लैटर्ज के बाद हमारी अधिकारियों की और रेलवे अधिकारियों की आपस मे मीटिग कराने की कोई स्कीम सरकार के पास है ?

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः अध्यक्ष महोदय, इस काम को कराने के लिए हमारा बराबर प्रयत्न जारी है और यह प्रयत्न बराबर जारी रहेगा।

सेठ लक्षमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय जी की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि करनाल मे रेलवे लाईन पर औवर ब्रिज बनाने का काम 4 साल पहले भाुरू हुआ था लेकिन वह अभी तक पूरा नही हुआ है।

श्री अध्यक्षः बजाज साहब, यह सवाल करनाल वाले पुल से ताल्लुक नही रखता।

सेठ लक्षमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल हरियाणा से संबधित है और करनाल भी हरियाणा मे ही है। मै इनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हू कि यह पुल पूरा न होने की वजह से वहा पर दो दो घटे ट्रैफिक जाम रहता है।

श्री अध्यक्षः बजाज साहब, जो बात आप कर रहे है वह तो ठीक है लेकिन आप जो सप्लीमैअरी पूछ रहे है वह इस मेन सवाल से ताल्लुक नही रखती। I think it is not possible to reply this question off hand Plaease take your seat.

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः स्पीकर साहब, आप की इजाजत से मै बजाज साहब को उनकी जानकारी के लिए बता ही देता हू कि सब जज की कोर्ट से इस पर स्टे हो गया है और 21. 3.1990 को इस तारीख लगी हुई है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूगा कि कितने आर0ओ0बीज0 बनाए जाते है इस वर्श कितने बनने की सम्भावना है और कितने समय अण्डर कन्स्ट्रूक ान है ?

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः– स्पीकर साहब, 4 आर0सी0 बीज0 सैक ाड है। मै इनके नाम बता देता हूंः–

(i) R.O.B at Sonepat.

(ii) R.O.B at Panipat on Assandh Raod

(iii) R.O.B at Panipat on Gohana Raod; and

(iv) R.O.B at Rewari Rohtak Raod.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि हरियाणा मे कितने रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने है, इन के

निमार्ण के लिए बजट मे कितना पैसा रखा गया है और क्या फरीदाबाद मे भी कोई रेजवे ब्रिज बनाया जाता प्रस्तवित है ?

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः– स्पीकर साहब, आर0ओ0बीज0 के लिए स्पै ाल प्रोविजन तो नही होता लेकिन सारे ब्रिजिज के लिए होता है। वर्श 1990–91 के लिए 4 करोड 35 लाख रूपये का प्रोविजन रखा गया है। वर्श 1989–90 मे 3 करोड 60 लाख रूपये का प्रोविजन पुलो के लिए था जिसमे आर0ओ0बीज0 भी भाामिल थे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया है। मैने इतने जानाना चाहा था कि कितने ब्रिजिज बनने प्रस्तावित है ? इसके अलावा फरीदाबाद के बारे मे गुंप्ता जी ने फरमाया था उसके बारे मे भी इन्होने कुछ नही कहा?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बडखल लेक को जो सडक जाती है उस पर ओवर ब्रिज बनाने की तयवीज है जिसके लिए आधा पैसा हुडडा दे रहा है और आधा पैसा रेलवे देगा। पुल सैक ान्ड हो चुका है और हमने भोयर जमा भी करा दिया है।

श्री बलबीर सिह चौधरीः अध्यक्ष महोदय स्टेट हाईवे न0 2 जो चण्डीगढ से सिरसा और चौटाला तक जाता है वह हरियाणा के 6 जिलों को आपस मे जोडता है। मै पी0डब्लयू0डी0 मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हू कि क्या इस सडक पर कैथल मे

रेलवे औवर ब्रिज बनाने की कोई प्रपोजल सरकार के विचारधीन है ?

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः– स्पीकर साहब, अभी कोई प्रपोजल नही है।

श्री सरबूल सिहः स्पीकर साहब, मेरे भाहर सफीदो मे नये बस अडडे का उदघाटन हो चुका है। रास्ते खराब होने के कारण बस अडडे पर पहुचने के लिए बसे बहुत तंगी पा रही है और लोगो को काफी दिक्कत है। इस अडडे का नक ाा भी बन गया है। मै माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि यह बस अडडा कब तक बन जाएगा या वह भी ऊत खाते मे ही जायेगा ? (हंसी)

श्री अध्यक्षः सरदार सरदूल सिह जो, रास्ता तो आप खुद भी बनवा सकते हो।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या कैथल मे औवर ब्रिज बनाने के लिए सरकार विचार करेगी?

श्री औमप्रका ा भारद्धाजः– स्पीकर साहब, विचार कर लिया जायेगा।

सेठ लक्ष्मन दास बजाजः स्पीकर साहब, करनाल के पुल टूटे हुए छ महीने हो गए है और उस पर काम अभी भाुरू ही हुआ

है। मै माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि यह पुल कब तक बन जाएगा ?

चौधरी औम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से श्री बजाज जी की तसल्ली के लिए उनको बताना चाहूगा कि जिस पुल का ये जिक्र कर रहे है वह पुल सिचाई विभाग का है और वह पुल बहुत तेजी से बन रहा है।

Women College at Mohindergarh

***1110 Shri Ram Billas Sharma:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to consturct a separate wing for women in Government College. Mohindergarh

(b) whether any amount has been deposited by the people with the Government for the construction of the aforesiad wing:

(c) if so, the total amount thereof togetherwith the period since when the said amount has been deposited; and

(d) if the reply to part (a) above be in teh affimative the time by which the aforesaid wing is likely to eb constructed?

ि ाक्षा तथा विकास मंत्री श्री हुक्म सिह:

(क) राजकीय महाविधालय, महेन्द्रगढ मे महिला बिग खोलने का मामला विचारधीन है। भवन निर्माण का प्र न विंग खोलने के निर्णय के उपरान्त ही उत्पन्न होगा।

(ख एवम ग) जी, हां 2.00 लाख रूपये की रा ि ा मास अप्रैल 1988 मे गर्ल्ज कालेज सोसाइटी, महेन्द्रगढ द्वारा उपायुक्त, महेन्द्रगढ के पास जमा करवाई गइ थी।

(घ) उपरोक्त भाग (ह) के उत्तर को दृश्टिगत रखते हुए भवन निर्माण के पूर्ण होने की तिथि का प्र ान उत्पन्न नही होता।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब मे बतलाया है कि नगर के लोगो ने दो लाख रूपये दो वर्श पहले अप्रैल, 1988 मे डी0सी0 महेन्द्रगढ के पास जमा करवाये थे। स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय तीन गुना मैचिग ग्रान्ट का सिस्टम भी था। मै जानना चाहता हू कि वह पैसा अब किस स्टेज पर है ? इसके अलावा क्या विभाग से इसमे कोई लापरवाही हुई है, अगर हुई है तो उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की तयवीज है ?

श्री हुक्म सिह: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि गर्ल्ज कालेज सोसयटी ने दो लाख रूपये डी0सी0 महेन्द्रगढ के पास जमा करवाये थे। श्री राम बिलास जी ने मैचिग ग्राट सी0एम0

रिलीफ फण्ड से दिलवाई थी। मै इन्हे बताना चाहूगा कि उस वक्त चुकि गलर्ज कालेज खोलने का विचार नही था इसलिए वह सारा पैसा डी0सी0 महेन्द्रगढ के पास जमा है।

सेठ लक्ष्मन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, करनाल मे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग ने गवर्नमैंट गर्ल्ज हाई स्कूल, गवर्नमैंट ब्यावज हाई स्कूल और गवर्नमैंट हाई स्कूल प्रेम नगर की बिल्डिगो को नाकार करान दे दिया है। क्या सरकार इन बिल्डिगो को बनाये जाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्षः बजाज साहब, महेन्द्रगढ और करनाल मे चूकि बहुत फर्क है इस लिए इस समय मंत्री जी द्वारा इसका जवाब औफ हैड दिया जाना संभव नही होगा।

श्री राम बिलास भार्माः क्या ि ाक्षा मंत्री महोदय इस काम को करवाने मे कोई तत्परता दिखारएगे ताकि यह बिल्डिग जल्दी से जल्दी बन सके ?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, सन् 1988 मे मांग आई थी कि यहां पर गर्ल्ज कालेज बनाया जाये और अब मांग आई है कि यहा पर गर्ल्ज विंग अलग से बना दयिा जाये। यह मामला सरकार के विचारधीन है और हम अलग से गर्ल्ज विंग वहां बना देगे और उस पैसे से बिल्डिग वहां बन जायेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, कोसली मे राजकीय कन्या महाविधालय खुलना था। इस कालेज के लिए कुछ

पैसा भी जमा हुआ था। मै आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि वह कालेज कब तक खोला दिया जायेगा ?

श्री हुक्म सिंहः इसके लिए ये अलग से नोटिस दे, जवाब दे दिया जाएगा।

श्री बंलबीर सिंह चौधरीः मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि पिछले दिनो रतिया के लोगो ने .....

Mr. Speaker: it is not possible to reply about Ratia as it does not ralate to this question. Please take your seat.

Counters at Bus-Stands

***1115 Shri Atma Singh Gill:** Will the Minister of State be for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open counters by The Haryana Tourism Corporation at Bus Stands on chandigrah Delhi highway to cater thge needs of the bus passengers in the State: and

(b) if so, the time bey which the aforesaid counters are likely to be opened ?

गृह मंत्री प्रो0 सम्पत सिंहः

(क) जी हां।

(ख) बस स्टैण्ड पिपली तथा पानीपत की सभी दुकाने पहले ही हरियााणा पर्यटन निगम को बस यात्रियो की सुविधा के लिए सौपी जा चुकी है । चण्डीगढ दिल्ली राज मार्ग के भोश बस अडडो को भी विभन्न चरणो मे हरियाणा पर्यटन निगम को सौप दिया जाएगा।

श्री हरनाम सिहः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि हरियाणा रोडवेज की बसो के अलावा बाकी बसे रास्ते मे जगह जगह रूकती है और ढाबो पर बस यात्रियो की खाल उतारी जाती है ? क्या आप प्राइवेट ढाबो पर कन्ट्रोल करेगे ताकि यात्रियों को न लूटा जा सके।

प्रो0 सम्पत सिहः हमने बाकायदा हिदायते दी हुई है कि ऐसे जगहो पर बसे न रोकी जहां पर बस स्टाप न हो, अगर बसे रूकती है तो इस वाकायदा कार्यवाही करेगे।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ट्रासपोर्ट विभाग, टूरिजम कार्पेरे ान की बसे अडडो पर काउन्टर सौप रहा है। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या हरियाणा टूरिजम के रेट हरियाणा की गरीब जनता के अनरूप है। क्या उनके लिए सस्ते भोजन का प्रबन्ध किया जाएगा?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा की जनता की भलाई को देखकर ही ऐसा किया गया है। अगर ट्रासपोर्ट

डिपार्टमैंट की सारी की सारी दुकाने टूरिजम वालो को दे दी जाती है तो सालान डेढ पौने दो लाख दो करोड रूपये का नुकसान हो सकता है क्योकि दुकाने औक ान होने से अच्छा पैसा आता है और टूरिजम वालो से हम सिर्फ 5000 रूपये ही लेते है। हमने जनता के लिये खाने पीने के लिये जो बन्दोबस्त किया है, मै उस बारे मे सारे हाउस की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हू कि वहा पर पूरी और भाजी चार रूपये मे दी जाती है। जूस का एक गिलास दो रूपये, दो पीस ब्रैड पकौडा दो रूपये मै और इसी तरह से दूसरी चीजे कन्सै ानल रेटस पर पब्लिक को दी जाती है। यह सब पब्ल्कि के हित की बात को ध्यान मे रखकर ही किया जा रहा है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि हम बस कन्डक्टरो/ड्राइवरों के खिलाफ कार्यवाही करेगे। मै उनसे यह पूछना चाहता हू कि अब तक किसी के खिलाफ आपने कार्यवाही की है। इसके अलावा जो प्राईवेट दुकाने रास्ते मे पडती है, उनमे चीजो की कीमत और क्वालिटी पर भी कोई क्न्ट्रोल करेगे ?

प्रो0 सम्पतं सिंहः स्पीकर साहब, प्राईवेट दुकानो की चीजो की कीमतो पर कन्ट्रोल करना मु कल है। जहां तक क्वालिटी की बात का ताल्लुक है, उसके लिये बाकायदा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमैंट वाले चैकिग करते रहते है। जंहा तक रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ ऐक ान लेने की बात है हम उन बस

ड्राईवर और कन्डक्टर्ज के खिलाफ कार्यवाही करते है जो हमारी इन्ट्रक ान्ज के बावजूद गलत जगह पर बस रोकते है।

श्री जय सिह राणाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने पूरी और सब्जी के रेटस और जूस के गिलास के रेटस बता दिये। मै इनसे यह जानना चाहता हू कि पूरियां कितनी मिलेगी और गिलास का साईज क्या होगा ?

प्रो0 सम्पतं सिंहः स्पीकर साहब, हम चार पूरियां देते है और सब्जी साथ देते है। एक बार ये खाकर देखगे तो आन्नद आ जायेगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हू कि क्या इनकी जानकारी मे है..... .....

श्री अध्यक्षः आप जानकारी की बात न कीजिए, सप्लीमैटरी पुट कीजिए।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, रेलवे मे एक रूपये मे तीन पूरियां मिलती है और हमारे यहां चार रूपये मे चार पूरियां मिले, यह कहा तक उचित है ?

प्रो0 सम्पत सिंहः एक रूपये मे तीन पूरियां नही मिलती । हम रेलवे से बढिया खाना देते है। बाकायदा सारी बात हमारी जानकारी मे है।

श्री परमानन्दः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि फूड एड सप्लाई डिपार्टमैंट वाले उनकी चैकिग करते है परन्तु यह काम तेा हैल्थ डिपार्टमैट वालो का है। क्या उन्होने ढांडा साहब की हैल्थ को देखकर तो यह बात नही कह दी है।(व्यवधान व भाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः ऐसी कोई बात नही है। जंहा तक प्योर फुडज का ताल्लुक है उसकी चैकिग हैल्थ डिपार्टमैंट करता है लेकिन अनाज और आटे वगैरह की चैकिग फूड एड सप्लाई डिपार्टमैंट करता है। (व्यवधान व भाोर)

खादय तथा पूर्ति राज्य मंत्री श्री नर सिंह ढाडाः आप परमानन्द की सेहत ही देख ले। इनकी सेहत मे कोई कमी तो आयी ही नही है।(व्यवधान व भाोर)

ताराकित प्र न सख्या 1128

यह प्र ान पूछा नही गया क्योकि माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय रावत इस समय सदन मे उपस्थित नही थे।

Mr. Speaker: Question list is over

अताराकित प्र न एवम उतर

New Buidings for Police Stations

192. Capt Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new buildings for the following Police Stations is Rewari consitituency:-

(i) Dharuhera,

(ii) Jatusana,

(iii) Rewari (Sadar): and

(b) if so, the tiem by which the aforesaid buildings are likely tobe constructed?

गृह मंत्री प्रो0 सम्पत सिहः

(क) (i) , (ii) हां, परन्तु इस समय उचित भूमि उपलब्ध नही है।

(iii) नही।

(ख) जब कभी उचित भूमि उपलब्ध होगी निमार्ण कार्य फन्डज की उपलब्धि के प्रावधान उपरात्न भाुरू किया जायेगा। इस तरह इस समय यह बताना कठिन है, कि इन पुलिस थानो के भवनो का किस तिथि तक निमार्ण होगा।

Income accrued form ausction of Liquor

195. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Agricultural be pleased to state the total income accrued form the auction of country made liquor and Indian made foreign liquor vends in teh State during the year 1989-90?

मुंख्य मंत्री चौधरी औमप्रका ा चौटाला: 128,137 करोड रूपये।

Harijan Chaupals

196. Capt Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Social Welfare to be pleased to state.

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following Harijan Chapuals in Rewari Costiruency:-

(i) Jadra,

(ii) Dakiya

(iii) Khatwali,

(iv) Rajipura

(vi) Ghatal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid chaupals anr likely to be constructed?

समाज कल्याण मंत्री श्री जगन नाथ:

(क) समाज कल्याण विभाग चौपालो के निर्माण का कार्य नही करता यह कार्य एक ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस उदे य के लिए रा ि ा विभिन्न विभागो द्वारा उपायुक्त के निपटान पर रखी जाती है जो स्वीकृति जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी है। जंहा तक समाज कल्याण विभाग का

सम्बन्ध है। ग्राम खतवाली के लिए 10,000 रूपये और ग्राम घाटल के लिये 20000 रूपये की रा ि ा दी गई है।

(ख) उपरोक्त (क) के दृश्टिगत प्र ान ही उत्पन्न नही होता।

Grain Market/Anaj Mandi at Dharuhera

197. Capt Ajay Sing Yadav: Will the Minister for Agriculture be pleased to state.

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Grain Market/Anaj Mandi at Dharuhera in District Rewari: and

(b) if so, the time by which the aforesaid market is likely to be opended?

मुख्यमंत्री चौधरी औम प्रका ा चौटालाः

(क) नही।

(ख) प्र न ही उत्पन्न नही होता ।

Punjab and Urdu Students/Teachers in Primary Schools

201. Shri Harnam Singh: Will the Minister for Education be pleased to state the total number of students studying s Punjab Urdu Language in the varuous schools in the State at present to getherwith the number of Punjab/Urdu teachers posted in these schools?

ि ाक्षा तथा विकास मंत्री श्री हुक्म सिंहः राज्य के विभिन्न स्कूलो मे पजाबी/उर्दू भाशा पढने वाले छात्रो तथा इन स्कूलो मे नियुक्त अध्यापको की सख्या निम्न प्रकार है–

1 विधार्थियो की सख्या

1.	पजाबी	56944
2.	उर्दू	4673

1 पढाने वाले अध्यपाको की सख्या

1.	पजाबी	404
2.	उर्दू	97

Construction of Buildings for Primary Schools

202. Shri Harnam Singh: Will the Minister for Eduction be pleased to state-

(a) whether there are any Primary Schools in Thanesar, Pheowa and Shahabad constituencies, which are without buildings; if so, the number thereof separately; and

(b) whether any amount has been sanctioned for the construction of new buildings and for repair of schools, as referred to in part (a) above, during the year 1989-90 if so. details therof ?

ि ाक्षा तथा विकास मंत्री श्री हुक्म सिहंः

(क) जी हां, विवरण निम्न प्रकार है:–

विधान सभा क्षेत्र	ऐसे राजकीय प्राथमि विधालयो की सख्या जिनके भवन नही है।
थानेसर	12
पेहवा	7
भााहबाद	19

(ख) जी हा, विवरण नीचे दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र	स्कूल का नाम	वर्श 1988.89 मे भवनो के निर्माण मुरम्मत के लिए स्वीकृत रा ि।
थानेसर	1. रा0प्रा0प0 लोहाडा	100000 रूपये
	2. रा0प्रा0प0 निवासरी	100000 रूपये
	3. रा0प्रा0प0 बडाचपुर	30000 रूपये
	4. रा0प्रा0प0 बहलोलपुर	30000 रूपये
	5. रा0प्रा0प0 सोढी	60000 रूपये

पेहवा	1. रा0क0प्रा0पा0 थाना	100000 रूपये
	2.रा0क0प्रा0पा0 गुथललागढ	100000 रूपये
	3. रा0क0प्रा0पा0 ई ााक	100000
भााहबाद	1. रा0प्रा0पा0 जोगी माजरी	50000 रूपये

Purchase of Oil Lever Filters

203. Shri Harnam Singh: Will the Minister of State for Cooperation be pleased to State-

(a) whether any oil Lever Filters have been purchased by the M.D Cooperative Sugar Mill, Shahabad during the year 1988; if so, the amount spent theron toghetwith the names of the firms which these were purchased; and

(b) whether any enquiry has been conducted about the said purchase of Oil Lever Filters during the same period; if so, the details thereof?

सहकारिता राज्य मंत्री श्री धीर पाल सिंहः

(क) मैसर्ज यूनीवर्सल हैवी इन्जीनियरिंग कम्पनी, सहारनपुर से वर्श 1988 मे 2.89 लाख रूपये की रा ि ा का एक ओलीवर फिल्टर ड्रम सहायक सामान सहित खरीदा गया था।

(ख) जी नही।

Rohit Minor

204. Shri Harnam Singh: Will the Minister for Irrigantion & Power be pleased to state-

(a) whether there is any shceme under consideration of the Government to construct the Rohit Minor of Thaska Meerangi Distributary: and

(b) if so, the time by which the aforesaid Minor is likely to be constructed?

मुख्यमंत्री मंत्री चौधरी औमप्रका ा चौटालाः

(क) हां ।

(ख) इस कार्या को पूरा करने के लिए कोई समय निर्धारित नही किया जा सकता क्योकि यह धनरा ि ा की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

Exevutive Officers for 'B' Class Municipal Committees

193. Seth Lachman Dass Bajaj: Will the Minister for Local Government be pleased to state whehter there is any proposal under consideration of the Government to appoint Exevutive Officers in 'B' Class Municipal Committees in the State?

स्थानीय भाासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): जी नही।

Government Aided and Privately managed Pharmacy Colleges

194. Seth Lachhman Dass Bajaj: Will the Chif Minister be pleased to state-

(a) the total number of Pharmacy Colleges function in the State togehterwith the number of studens enrolled therin;

(b) the number of colleges out of those as referred to in par (a) above, are Government aided or privately managed, separately; and

(c) whether any case of demanding the donations by the management of the aforesiad colleges form the students at the time of admission came to the notice of the Government; if so, the steps taken or proposed to be taken to check this malpracticos ?

मुख्य मंत्री (चौधरी औमप्रका ा चौटाला):

(क) हरियाणा मे 13 सस्थाये फार्मसी डिप्लोमा कोर्स चलाती है। इनकी वार्शिक प्रवे ा क्षमता 940 है।

(ख) 7 सस्थाये सरकारी है, 5 सस्थाये गैर सरकारी बिना सहायता और एक गैर सरकारी सहायता प्राप्त सस्था है।

(ग) जी हा, कुछ ि ाकायते सरकार के ध्यान मे आई। इन सस्थाओ द्वारा गैर कानूनी दान डोने ान कैपीटे ान फीस लेने की कुप्रथा को रोकने के लिये सरकार ने इस सस्थाओ के लिए फीस की दरे निर्धारित की है। वर्श 1988–89 मे सभी सस्थाओ के लिये केन्द्रित दाखलों की प्रणाली भाुरू की गई थी। 4 गैर सरकारी, बिना सहायता प्राप्त सस्थाओ ने केन्द्रित दाखलो की इस प्रणाली को स्वीकार नही किया और एक सस्था ने इसे पजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय मे चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। सरकार ने इस निर्णय के विरूद्ध अपील दारय की, जो न्यायालय के निर्णायर्थ लम्बित है उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय की स्टेप्रदान की हुई है।

विभिन्न विशयो को उठाया जाना

डा0 मंगल सैनः स्पीकर सर, मैने आज एक काल अटै ान मो ान दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात को जरा गोर से सुने। पिछले दिनो अखबारों मे आया था और आज भी इडियन ऐक्सप्रैस के तीसरे सफे पर छपा है कि चौधरी देवी लाल ने एक सीनियर आई0ए0एस0 औफिसर को अपने साथ लगाया था लेकिन अब उनके छोटे सपुत्र ने उनके विरूद्ध पचकूला के किसी प्लौट की अलौटमैट सम्बन्धी रिकार्ड को टैम्पर विद करने का इलजाम लगाया है और उसको हटवाने के प्रयास मे है। The entire Government has become a laughing stock becuases of it. The Government must come forward with a statement and clarify the matter.

Mr. Speaker: I have disallowed it.

श्री हरनाम सिहः स्पीकर साहब, मेरा एक ऐडजर्नमैट मो ान है। सारे हरियाणा के आठ जिलों मे एक साल से वकीलो की हडताल चल रही है। लोग परे ाान है, जुडीि ायल पैरेलाईज हो रही है। और लोग जेलो मे पडे है। किसी मुकदमे का कोई फैसला नही हो रहा है। सरकार ने इसके लिये कुछ नही किया है। मेरी अर्ज यह है कि मेरा यह ऐडजर्नमैंट मो ान ऐडमिट किया जाये।

Mr. Speaker: Dr. Sahib. I have disallowed it also.

डा0 मंलग सैनः स्पीकर साहब, मेरे काल अटै ान मो ान का क्या हुआ?

Mr. Speaker: Doctor Sahib, I have told you that I have disallowed that.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे सुनने मे भाायद कमी रह गई। It is a very important matter, Sir.

श्री अध्यक्षः उस वक्त भाायद आप यह भूल गए थे कि यह बडा इम्पोर्टैन्ट मैटर है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मै भूला नही था लेकिन कई बार हमारी तरफ आपकी नजरे इनायत नही होती ।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, ऐसी कोई बात नही है But as I have told you, I have disallowed it.

डा0 मंलग सैनः फिर तो आपने अच्छा नही किया।

Mr. Speaker: Doctor Sahib, It is most unfortunate that a very senior ligislator like you should make such a remark.

Dr. Mangal Sein: Sir, I wihtdraw these words.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have reveived a notice of calling attention motion No. 18 from Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A regarding falling down of ground water level in the distircts of Mohindergarh and Rewari. I admit it. अब कैप्टन अजय सिंह, एम0एल0ए0ए0 अपना नोटिस पढ दे और उसके बाद कन्सर्ड मिनिस्टर यदि स्टेटमैट देना चाहे तो दे दे।

Capt. Ajay Singh Yadav: Mr, Speaker, Sir, I want to draw the attention of this August House that the watertable in the districts of Mahendergarh and Rewari is falling continuoulsy, due to which water of wells is drying up and farmers are facing many difficulties in irrigating their lands. Drinking water problem is alos becoming serious. The land becomes barren in case it is being irrigated by the water of wells as the same is saline one, Both these districts are being deprived of irrigation for not giveing electric connections to pump houses inspite of having the supply of canal water through Jawahar Lal Nehru Canal and Mahendergarh Canal. Animals alos are not getting suffcient drinking warer, The ponds have been dried up. The supply of drinking water depends upon the water of wells in the villages and cities

water depends upon the water of wells in the villages and cities of district Mahendergarh and Rewari. The drinking water schemes have become useless due to the fall in water table. In both the districts farmers are faving a great diffiuclty for not having the Lining of water courses provided for cnaal irrigation. Both districts are getting less of water from the available canal water.

I therefore, request that the electric connection be given to all the pump houses of Jawahar Lal Nehru Canal and Mahendergarh Canal and Canal water in more quantity be supplied immediately for drinking as well as for irrigation pruposes so that the dry fields of these districts be irrigated and the concerned Minister may clarify the position in the House by making a statement after taking immediate action in the matter.

वक्तव्य

सिचाई तथा बिजली राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

सिचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (श्री सचदेव त्यागी): जिला महेन्द्रगढ तथा रिवाडी मे, 1974 से 1989 तक, भूमिगत जल का स्तर औसतन 5 मीटर तक नीचे गिर गया है। जल स्तर गिरने के मुख्य कारण भूजल स्त्रोतो से पानी की अधिक निकासी उथले नलकूप तथा पम्पिग सैट द्वारा जिनकी सख्या इस दौरान 18000 से लगभग 41000 हो गई है। औसतन वर्शा की कमी के साथ साथ

कुछ वर्शो से भारी सूखे की स्थिति और राजस्थान द्वारा साहिबी, कृश्णावती तथा दोहान, बरसाती नदियों पर बनाये गये जलघर है।

2. धरातल जलस्तर के गिरने के उत्पन्न हुई कठिनाइयों से निपटने के लिए, राज्य सरकार से नीचे लिखे उपाय किये है:—

(1) इन जिलो के लिये बनाई गई जवाहर नेहरू सिचाई योजना रबी के दौरान कोई सिचाई की सुविधा नही रखती जब तक कि राबी ब्यास का फालतू पानी उपलब्ध नही होता जो कि सतलुज यमुना नहर के पूरा होने के उपरान्त उपलब्ध होगा। 1979 से पानी की सुविधा रबी की फसल के लिये भी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नही राजय सरकार ने पिछले तीन सालों से पानी की सुविधा बढाने के लिए वि ोश प्रबन्ध किये है जिसमे 1986—87 मे करीब 1.33 लाख क्यूसिक दिनों से बढाकर 1989—90 20 मार्च 1990 तक मे 1.79 लाख क्यूसिक दिन हो गये है। इसके फलस्वरूप सिचित भूमि भी इस दौरान 43299 एकड से बढकर 60968 एकड हो गई है।

(2) जवाहर लाल नेहरू योजना का निमार्ण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इन जिलो के 80 पम्प घरों मे से 48 पम्प घरों को बिजली देकर चालू कर दिया गया है जिनमे से 25 पम्प घरों को वि ोश कर पिछले तीन वर्श मे बिजली देकर चालू किया गया है।

(3) केवल 8 गावों को छोडकर जो कि चार प्रति जिला है, भोश समस्त गावों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गइ है। लगभग तीन साल पहले पीने के पानी की स्थिति सन्तोशजनक नही थी और अधिकतर गावों मे पीने के पानी की उपलब्धि एक दिन छोडकर होती थी। पिछले तीन सालो मे सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओ के अन्तगर्त इन दोनो जिलो मे 102 नलकूप लगाये गये है जिसके माध्यम से पीने के पानी की कथित गावो की सुविधा बढी है। इसके इलावा एक पीने के पानी की योजना नारनौल भाहर के लिए बनाई गई है जिसमे पीने का पानी नहर से उपलब्ध कराया जाता है।

(4) जहां तक प ाुओ के लिए पीने का पानी देने का सम्बन्ध है सरकार ने इस सम्बन्ध मे पिछले तीन वर्शो मे वि ोश ध्यान दिया है। ओर समय समय पर नहर से गावो के जोहड भरे है। जंहा कही भी गावों की पचायतो ने खाले बनाकर दूर दराज के जोहडो को भरने के लिए कहा, वहां पर अस्थाई मोगे लगाये गये और जोहड भर दिये गये।

3. जो कुछ अब तक हुआ है, राज्य सरकार को उससे सतोश नही है। इस समस्या की गहराई को समझते हुए सरकार नीचे लिखे कदम उठाना चाहती है:–

(1) उन क्षेत्रो मे जहां के पानी की उपलब्धि की स्थिति काफी खराब है मै पडने वाले पम्म घरों को उच्चतम स्तर पर विधुतीकरण करने हेतू प्रयत्न किये जायेगे।

(2) सतलुज यमुना लिंक नहर की पूर्णता पर रावी ब्यास पानी के प्राप्त होने के प चात नहरो मे पानी की उपलब्धि बढाने के साथ साथ पेय जल जहां तक सम्भव होगा, देने की योजना को बढाव दिया जायेगा।

(3) राजस्थान सरकार से उस समस्या को लेकर जो कि उन द्वारा साहबी, कृश्णावती और दोहान दरियाओ पर पानी इकटठा करने के स्त्रोतो के कारण उत्पन्न हुई है, पर बातचीत की जा रही है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान सरकार से प्रयत्न तब तक जारी रखे जायेगे जब तक कि सतोशजनक स्थिति उपलब्ध नही हो जाती।

(4) जवाहर लाल नेहरू परियोजना को चाले करने सम्बन्धी, जब तक कि फालतू न प्रयोग होने वाला यमूना नदी का पानी उपलब्ध रहेगा के बारे मे प्रयन्त जारी रखे जायेगे। इसके साथ साथ कम हो रहे भूजल स्तर को पुन चार्ज करने सम्बन्धी योजनाओ पर विचार जारी रहेगा।

(5) सतलुज यमुना लिंक परियोजना का पूरा करवाने सम्बन्धी सभी प्रयत्न किये जा रहे है ताकि जवाहर लाल नेहरू परियोजना को इसके हिस्से के पानी की उपलब्धि जो कि रावी

ब्यास के फालतू पानी से प्राप्त होनी है, हो सके,। इसके प चात यह परियोजना अधिक डिस्चार्ज तथा रबी समय मे लबी अवधि तक उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ भूजल स्तर की कमी को काफी लम्बे क्षेत्र मे पुन स्तर पर लाने हेतू प्रयत्न भी जारी रहेगे।

4. जवाहर लाल नेहरू परियोजना मे और अधिक पानी की उपलब्धि तब तक सम्भव नही होगी जब तक कि सतलुज यमुना लिंक परियोजना पूरी तकर निर्मित नही हो जाती।

5. जंहा तक खालो को पक्का करने का सम्बन्ध है, इन जिलो के यह कार्य वर्श 1998 मे चालू कर दिया गया था अब तक 4.58 लाख चालू फुट खालो की लम्बाई पक्की कर दी गई है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, सरकार पिछले 10 वर्शा से वर्शा न होने के कारण महेन्द्रगढ तथा रिवाडी जिलो मे भूमिगत पानी का स्तर लगातार नीचे गिर गया है और राजस्थान सरकार ने साहबी नदी, कृश्णावती नदी तथा दोहान नही के ऊपर छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोक लिया है और वह पानी इधर हरियाणा को और नही आ रहा है।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप सवाल कीजियेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि सरकार ने भूमिगत जल स्तर को ऊंचा के लिये राजस्थान, सरकार से कितनी बार बातचीत की है ताकि हमारे हिस्से का पूरा

पानी हमे मिल सके ? सरकार इस बारे मे अपनी स्थिति स्पश्ट करे।

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, बातचीत चल रही है, आखिरी दौर पर है लेकिन अभी कोई डिसीजन नही हो पाया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा कि पानी अभी अधिक मात्रा मे नही मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, करनाल, सोनीपत और रोहतक जिलों मे काफी वाटर लोंगिग है। क्या दूसरे इलको के भूमिगत जल स्तर को ऊंचा लाने के लिये अथवा इस उपलब्ध जल की री चार्जिग करके इसे नहरो मे छोडने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है ताकि वाटर लौग्ड एरिया मे वाटर की री चार्जिग हो जाए, दूसरे इलाको मे वाटल लैबल ऊपर आ जाए और जरूरतमन्द लोगो को सिचाई के साधन आसानी से उपलब्ध हो सके ?

श्री सचदेव त्यागीः इस के बारे मे लिखित उतर दे दिया गया है कि सतलुज यमुना लिंक नहर की पूर्णता पर रावी ब्यास पानी के प्राप्त होने के बाद नहरों मे पानी की उपलब्धि बढाने के साथ साथ पेय जल जंहा तक सम्भव होगा, देने की योजना को बढावा दिया जायेगा। मै यह भी बताना चाहता हूं कि जे0एल0एन0 कैनाल साल मे केवल तीन महीन जुलाई, अगस्त और सितम्बर मे टैम्पोरेरी फक्सन करती है। जब एस0वाई0एल0 का पानी आ जाएगा तभी यह नहर लगातार चल सकेगी। जो यमुना का पानी

बरसात के दिनो मे इक्टठा होता है उस पानी को आव यकता के अनुसार इलाके मे दिया जाता है। अब हम इस बात पर भी विचार कर रहे है कि बगैर डिमांड के भी पानी उधर दिया जाए।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

पक्की ईटो की कीमतो मे वृद्धि के कारण लोगो मे भारी रोश होने सम्बन्धी

Mr. Speaker. Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 19 from Shri Harnam Singh, M.L.A regarding great resentment amongst the people due to increase in the price of pucca bricks. I admit it. He may please read his notice and the Minister concerned may make a statement thereafter.

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, इस महान सदन का ध्यान इस विशय की और दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा मे पक्की ईटों का भाव 6000 रूपये प्रति हजार से बढ कर 750 रूपये मे 800 रूपये प्रति हजार हो गया है जबकि सरकार ने पक्की ईटो की कीमत 600 रूपये प्रति हजार तय की हुई है। कीमतो मे वृद्धि के कारण भवन निर्माण कार्य बहुत प्रभावित हुआ है। इस कारण लोगो मे बहुत बैचनी है। यदि ईटो को उचित दर पर सप्लाई करने का प्रबन्ध नही किया गया तो इसका समाज पर बुरा प्रभाव पडेगा। अतः मै निवेदन हूं कि सरकार इस मामले मे तुरन्त कार्यवाही करके तदानुसार सदन को सूचित करे।

वक्तव्य

खाध तथा पूर्ति राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बनधी

खाध तथा पूर्ति राज्य मंत्री (श्री नरसिंह ढाडा): स्पीकर साहब, पिछले वर्श सरकार के नोटिस मे आया था कि ईटो के भाव बहुत बढ गये है। और भटठा मालिक राज्य से बाहर ईटो को भेजकर ईटो की कमी पैदा कर रहे है। इस स्थिति को मध्ेनजर रखते हुये राज्य सरकार ने हरियाणा कन्ट्रोल औफ ब्रिकस सप्लाईज आर्डर, 1972 की धारा 10 तथा 11 के अन्तर्गत ईटो की सिलिग प्राईसीज निर्धारित कर दी और ईटो के राज्य से बाहर से जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। ईटो के सिलिंग रेट दिनांक 5.9. 1989 से भटठा स्थल पर सभी टैक्सो सहित प्रति एक हजार निम्न प्रकार निर्धारित किये गये थे, जिसमे परिवहन, ईटो की लदाई तथा उतरवाई भाामिल नही है:–

1.	प्रथम श्रेणी	600.00 रूपये
2.	द्वितीय श्रेणी	530.00 रूपये
3.	तृतीय श्रेणी	460.00 रूपये

उक्त अकु ा अभी भी राज्य मे लागू है व सरकार का ईटो के विक्रय भावो पर नियन्त्रण है तथा ईटो के राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध है। जो कार्यवाही हरियाणा मे ईटो के भावों

को बढने से रोकने के लिए की गई है ऐसी कार्यवाही हरियाणा के साथ लगते राज्यों उत्तर प्रदे ा, दिल्ली, राजस्थान तथा पजांब किसी मे नही की गई है।

उपरोक्त के साथ साथ यह सुनि चत करने के लिए कि ईटे सिलिंग भाव पर उपलब्ध हो और भटठे वाले ईटों का राज्य से बाहर निर्यात न करे, जिलाधी ा/जिला खाध तथा पूर्ति नियन्त्रको को हिदायते दी गई है कि सरकार द्वारा जारी आदे ाो की कठोरता से पालना की जाये और दोशी पाये जाने वाले भटठा स्वामियो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध मे विभिन्न जिलाधी ाो/जिला खादय तथा पूर्ति नियन्त्रक द्वारा समय समय पर दोशी भटठा मालिको के विरूदघ कार्यवही की गई है। यह सुनि चत करने के लिए कि सरकारी उपभोग्ता विभागो के निमार्ण कार्यो मे कोई बाधा न पडे, जिलाधी ाो द्वारा परमिट प्रणाली के माध्यम से उन्हे ईटे उचित भाव पर उपलब्ध करवाई गई है और इस विभागो से सिंलिग रेट निर्धारित करने के प चात कोई ि ाकायत प्राप्त नही हुई है। जब जब किसी उपभोग्ता द्वारा अधिक रेट लेने बारे ि ाकायत की गई है, विभाग द्वारा उस भटठा मालिक के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

इस वर्श लगभग 257 भटठे राज्य मे स्थापित किये गये है। इस प्रकार इस वर्श राज्य मे 1496 भटर्ठ ईट निर्माण मे कार्यरत है जबकि पिछले वर्श इनकी संख्या 1239 थी। यह सत्य है

कि इस वर्श ईटो के उत्पादन पर असामायिग वर्शा होने के कारण बुरा प्रभाव पडा है और ईटो का उत्पादन कुछ कम हुआ है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से ईटो की उपलब्धता व मूल्यो की स्थिति बारे रिपोर्ट मंगवाई जाती है और जिला खाध तथा पूर्ति नियन्त्रको द्वारा यही सूचना दी गई है कि जिले मे ईटे निर्धारित मूल्य 600.00 रूपये प्रति 1000 ईटे, पर उपलब्ध है।

इस वर्श असामायिक वर्शा के कारण ईटो के उत्पादन मे कमी आई है और यह सम्भव है कि ईटो की उपलब्धता मे उपभोग्ताओ को कुछ दिक्कते आ गई होगी। इस स्थिति को नियन्त्रण मे करने के लिए सरकार द्वारा निर्दे ा जारी किये गये है कि हरियाणा कन्ट्रोल औफ ब्रिकस सप्लाईज आर्डर, 1972 की पालना और अधिक सख्ती से की जाए ताकि ईटो का निर्यात राज्य से न हो और उपभोक्ताओ को निर्धारित मूल्य पर ईटे मिल सके। विभाग द्वारा इस उपलब्ध मे कोई भी ि ाकायत मिलने पर तुरन्त सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी इस बात के लिए उचित कार्यवाही करेगे कि जितनी ईटे पैदा होती है, वे सिविल सप्लाई महकमे के कन्ट्रोल के अन्डर लोगो को ठीक रेट पर दी जाएगी ?

श्री नर सिह ढाडाः अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रस्ताव अभी सरकार के विचारधीन नही है क्योकि इसमे बडा भारी दिक्कत

आती है। एक एक कज्यूमर को परमिट काट कर देना पडता है और भटठे से ईट दिलानी पडती है इसलिए यह मुमकिन दिखाई नही दे रहा है।

श्री हरनाम सिहः फिर यह जो आपने भरोसा दिलाया है कि ठीक रेट पर ईट दिलाई जाएगी, वह अमली रूप मे कैसे आएगा ?

श्री नर सिंह ढाडाः अध्यक्ष महोदय, जंहा कही भी कोई कज्यूमर ि ाकायत करता है कि मेरे को ईट इस भाव पर नही मिल रही है, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि ि ाकातयकर्ता की ि ाकायत पर जब इन्क्वायरी होती है तो उस समय वह अपनी ि ाकायत को वापिस ले लेता है और कह देता है मुझे कोई ि ाकायत नही है। हमने महकमे को आर्डर दे रखे है कि इस प्रकार की ि ाकायत सुनने मे न आए। पिछली 5 तारीख तक हमने पूरे हरियाणा के भटठो की इन्कवायरी की जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है इस बारे मे एफ0आई0आर0 तक भी लौज की गई है।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 121 के तहत रूल 30 को सस्पैड करने के लिए मो ान मूव करेगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 29th March, 1990.

Sir, I also move

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 29th March, 1990.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 29th March, 1990.

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 29th March, 1990.

श्री हरनाम सिहः अध्यक्ष महोदय, मै अर्ज करना चाहता हू कि वीरवार का दिन गैर सरकारी कार्य के लिए रखा हुआ है लेकिन इस सारे सै ान मे पिछला वीरवार भी इस तरह से खत्म कर दिया था और इस विरवार को भी इसी तरह से खत्म किया

जा रहा है। मै समझता हूं कि इस तरह करने से माननीय सदस्यो के अधिकार का हनन नही होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, बिजैनस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन ने ऐडौप्ट कर ली है। इसलिए रिपोर्ट सदन द्वारा ऐडौप्ट करने के बाद यह प्र न पैदा नही होता । आज के दिन सरकार कार्य करने के लिए 10 दिन पहले ही फैसला हो चुका था।

डा0 मंगल सैन रोहतकः स्पीकर साहब, आपने बजा फरमाया है कि आज के दिन सरकारी कार्य करने के लिए 10 दिन पहले ही सदन मे बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ऐडौप्ट कर ली थी। लेकिन, स्पीकर साहब, वह रिपोर्ट ऐडौप्ट करने के बाद ही आज यह मो ान लाया गया है और हमे इस पर बोलने का अधिकार है। आप इस बात को ऐग्री करेगे। हमारी हम्बल सबमि ान है कि democracy runs by deliberations. अगर डेलीब्रे ान नही होगा तो डैमोक्रेसी नही होगी। यह गवर्नमैट बहुत मजबूत है और बडे बडे अच्छे आदमी के हाथ मे है। अगर आज का दिन नौन औफि ियल डे कर दिया जाए तो गैर सरकारी काम हो जाएगा और भाई सम्पत सिंह को भी बोलने का मौका मिलेगा। हमे भी बोलने का मौका मिलेगा और सब अपनी बात कर सकेगे। इस तरह से सारा हाउस ऐनलाइटन होगा। हाउस के माध्यम से सारे प्रदे ा की जनता को पता लगेगा । अगर हम लोग बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ऐडौप्ट कर चुके है तो कोई

बात नही अगर हमारी बात मान जाए तो आपकी बडी कृपा होगी वरना वोट तो हमे देना ही पडेगा।

श्री कैला ा चन्द भार्मा (नारनौल): स्पीकर साहब, सारे साल मे दो सै ान होते है और सै ान के दौरान वीरवार का दिन गैर सरकारी काम करने के लिए मिलता है। मैने आपकी सेवा मे हरियाणा ऐडवोकेटस वैल्फैयर बिल दिया हुआ है। मै चाहता था कि आज मुझे उस पर बोलने का अवसर मिलेगा परन्तु आज का दिन नौन औफि ायल डे की बजाय औफि ायल बिजैनस डिस्कस करने के लिए कनवर्ट कर दिया गया है। इस तरह मुझे उस पर बोलने का मौका नही मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, आपका वह बिल मैने गवर्नमैट के पास भेजा हुआ है। जंहा तक आज के दिन सरकारी कार्य करने की बात का ताल्लुक है, हमारे पास केवल एक रैजोल्यू ान है जो पिछले दो साल से चला आ रहा है, उसके बाद कोई रैजोल्यू ान नही आया। एक कारण यह भी था इसलिए आज का दिन नौन औफि ायल डे की बजाय औफि ायल बिजनैस डिस्कस करने के लिए कनवर्ट किया गया है।

गृह मंत्री प्रो0 सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक टाईम की बात है, आपने सभी को बोलने के लिए पूरा टाईम दिया है। अध्यक्ष महोदय नौन औफि ायल बिजनैस न होने की वजह से यह दिन औफि ायल बिजनैस डिस्कस करने के लिए कन्वर्ट

किया गया है। अगर कोई नौन औफिि ायल बिजनैस होता तो हमे कोई एतराज नही था।

Mr. Speaker: Question is

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 29th March, 1990.

&

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 29th March, 1990.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के तहत मूव करेगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly' indefinitely.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुए–

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मूव करेगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move

That the Assemble at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुए–

कि असैम्बली अपनी आज बैठक के उठने पर साईन डाई ऐडजर्न होगी।

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि असैम्बली अपनी आज बैठक के उठने पर साईन डाई ऐडजर्न होगी।

प्रस्ताव स्पीकृत हुए।

समितियो की रिपोर्टस पे ा करना–

(i) कमेटी औरन सबौडिनेट लैजिसले ान की 21वी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी औन सबौडिनेट लैजिसले ान के चेयरमैन, श्री सुरेन्द्र, कमेटी की वर्श 1989–90 के लिए 21वी रिपोर्ट पे ा करेगे।

Shri Surinder (Chairman, Committee on subordinate Legislation): Sir. I beg to present the Twenty First Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1989-90.

(ii) कमेटी औन दि वैल्फेयर औफ भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज की 15वी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी औन दि वैल्फेयर औफ भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज के सदस्य श्री भागमल, कमेटी की वर्श 1989–90 के लिए 15वी रिपोर्ट पे ा करेगे।

श्री भागमल, कमेटी(सदस्य औन दि वैल्फेयर औफ भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज): अध्यक्ष महोदय मै कमेटी औन दि वैल्फेयर औफ भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज कमेटी की वर्श 1989–90 के लिए 15वी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

बिल्ज

(i) दी हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमैट) बिल, 1990

Mr. Speaker: Now, the Local Government Minister will in traduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1990 and also move for its consideration.

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मै दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमैट) बिल, 1990 को प्रस्तुत करता हू।

मै यह भी प्रस्ताव करता हूं–

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमैट) बिल, पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री कैला ा चन्द भार्मा (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, मै इस बिल का समथर्न करने के लिए खडा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि नगरपालिकाओ की आय के जो साधन है, वे बहुत समय पहले तय किए गए थे और उस हिसाब से जो आय नगरपालिकाओ की होनी चाहिए थी वह नही हो पाई। इस समय बहुत सारे लोगो के पास नगरपालिकाओ की रा ि ा बकाया पडी है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन हमारी सभी नगरपालिकाओ खास

कर जेा (बी) और (सी) श्रेणी की नगरपालिका है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। यदि हम इन नगरपालिका न कह कर कर्मचारीपालिका कहे तो कोई अति योक्ति नही होगी। ये नगरपालिका सारी कोि ा ा करने के बाद जो आय कर पाती है, उससे ये सिर्फ अपने कर्मचारियो को तनख्वाह ही दे पाती है। कई बार हालात यह भी हो जाती है कि ये नगरपालिकांए दो–दो, तीन–तीन महीनों तक अपने कर्मचारियो को तनख्वाह भी नही दे पाती । अगर ये तनख्वाहे ही न दे पांएगी तो विकास के कार्य तो गौण हो ही जाते है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि थोडा अकु ा लगने से म्यूनिसिपैलिटीज की आय बढेगी, इसलिए मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि एक बार इस नगरपालिकाओं पर गम्भीरता से विचार कर के कार्यविधि तैयार करे। पहले नगरपालिकाओ के पास 2–3 साधन आय के थे। एक तो डिवैल्पमैट चार्जिज आते थे और दूसरे मकाने के नक ो वगैरा पास करके कुछ आमदनी कर लेती थी लेकिन आज नगरपालिकाओ की स्थिति ऐसी हो गई कि यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका के पास नक ाा पास करवाने के लिए जाता है तो नगरपालिका के कर्मचारी यह कर टाल देते है कि नक ाा पास करने का हमे अधिकार ही नही है और नक ाा वापिस कर देते है। गावों के लोग रोजगार की तला ा मे भाहरो मे आते है। यह स्वाभाविक है कि भाहर मे रहने के लिए उनको मकान भी चाहिए। जब उनके नक ो पास नही होते तो स्वाभाविक रूप से व अनऔथोराइज्ड कान बनायेगे और इस प्रकार अनऔथोराइज्ड कालोनीज बन रही है। आज कोई

भी ऐसा नगर नही है जिसके आसपास अनऔथोराइज्ड मकान न बने रहे हो। इसका कारण यह है कि हम उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था नही कर पाते। आज नगरपालिकाओं की आय समाप्त हो गई है और जो डिवैल्पमैट चार्जिज मिलते थे वे भी समाप्त हो गए है। हम लोगो के सामने भी कई समस्याए खडी हो गई है। जब हम किसी बात को ले कर उन लोगो के सामने भी कई समस्याए खडी हो गई है। जब हम किसी बात को ले कर उन लोगो के सामने जाते है या वोट लेने के लिए जाते है तो लोग खडे हो जाते है और कहते है कि हमारी कालोनी मे पीने का पानी नही है, सडक नही है, नालियां नही है। जब हम कहते है कि क्या आपने डिवैल्पमैट चार्जिज दिये है तो उनका जवाब होता है यह चार्जिज लेने वाला ही नही कोई नही है। चार्जिज देने वाले के सामने समस्या खडी कर जाती है कि टाउन एण्ड कट्री प्लानिंग से कोई लैटर आया हुआ है। कि भाहर की सीमा निर्धारित करेगे तक चार्जिज लेगे। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा का सदस्य बने हुए मुझे तीन साल हो गए है लेकिन 3 साल से उनके पास यही एक जवाब है। सीमा निर्धारित करने के लिए उनसे बार बार कहा गया, और पूछा गया कि सीमा कब तक निर्धारित करनी है, कितना समय लगेगा, इसके लिए कोई व्यवस्था तो कीजिए ? इसलिए अध्यक्ष महोदय मै मंत्री महोदय से अनुरोध करूगा कि नगरपालिकाओ की सीमा कब निर्धारित होगी, नक ाा कब पास करेगे, इसके लिए कोई व्यवस्था करे। इतनी ही मेरी प्रार्थना है। जंहा नगर पालिकाओ की आय बढाने के लिए यह बिल लाया गया है वहां

इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि नगरपालिकाओ की सीमा बढाने के लिए कोई तरीका अपनाया जाये।

श्री अध्यक्षः कैला ा जी, अब आप कृपया बैठे।?

श्री कैला ा चन्द भार्माः अध्यक्ष महोदयख मै एक और बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हू। जिस प्रकार क्षेत्रो मे पिछडे वर्गो के लोगो को मकान बनाने के लिए पचायते भूमि देती है, उसी प्रकार भाहरो मे भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग रोजगार की तला ा मे भाहरो मे आते है, उनमे जो पिछडी जाति के हरिजन बन्धु है, उनके लिए भी नगरपालिकाओ को अधिकार दिए जाए कि वे भी अपने क्षेत्रो मे गरीब आदमियो और हरिजनो को मकान बनाने के लिए प्लाट दे ताकि वे ठीक प्रकार से रहे सके। इस प्रकार की व्यवस्था भी नगरपालिकाओ मे होनी चाहिए। धन्यवाद।

सेठ लक्ष्मन दास बजाज (करनाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मै म्यूनिसिपिल कमेटियों के बारे मे 2–4 बाते कहना चाहता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव हाऊस टैक्स और मार्किट टैक्स की बकाया रा ि ा की वसूली के बारे मे है। इन टैक्सो के बकायता की वसूली करने का हमारे पास कोई प्रबन्ध नही है, इन के लिए कोई प्रबन्ध किया जाए। इसके साथ ही जिन लोगो ने 30–35 साल से भाामलता देह जमीन पर

कब्जा कर रखा है, जिसका उन्हे कोई हक नही, उसके लिए कोई न कोई कानून बनाया जाए जिसके तहत कमेटियां उनसे पैसा से सके और म्यूनिसिपल कमेटियां चल सके। ऐसी जमीन सैकडो नही हजारो एकड पडी है। केवल करनाल मे चौथाई हिस्सा ऐसी भाामलात देह जमीन पडी है जिस पर लोगो का नायाजब कब्जा हैं। इस जमीन का पैसा न तो सरकार को मिला है और न ही म्यूनिसिपल कमेटियो को मिला है। नगरपालिकाओं से सैकडो केस अदालतो मे पडे है। मेरी म्यूनिसिपल कमेटी मे 200–250 केसिज पिछले डेढ से तीन साल के समय पैडिग पडे है। इस प्रकार के केसों का भी कुछ न कुछ हल होना चाहिए ताकि ये फैसले जल्दी से जल्दी हो सके। स्पीकर साहब, इसके साथ ही मै एक और चीज कहना चाहता हूं । हाउस मे तो हम कोई चीज पास कर देते है लेकिन सरकार उसकी इम्पलमैटे ान प्रोपर नही करती। हमने हाऊस मे पास कर दिया कि श्री व्हीलर और फोर व्हीलर खरीद जाए लेकिन जब इस बारे गवर्नमैंट को लिखते है तो उस मे 6 महीने, 8 महीने या साल का समय लग जाता है। मै निवेदन करूगा कि इसका अधिकार डी0सीज0 को दिया जाए ताकि हम उनके थ्रू जल्दी खरीद करे और हमारा काम चल सके। हमारे भाहर मे सफाई की हालत भी बहुत खराब है, उसके बारे मे भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मै रिफयूज कलैक्टर की बाबत भी करना चाहता हूं। रिफयूज कलैक्टर तकरीबन 5 लाख रूपये का आता है जो म्यूनिसिपल कमेटिया खरीद सकती है लेकिन खरीदने की इजाजत नही है। इसलिए

निवेदन है कि उन्हे खरीदने की इजाजत दी जाए। जब कभी सरकार को लिखा जाता है तो सरकार से इजाजत मिलने मे कम से कम एक साल का समय लग जाता है।

श्री अध्यक्षः अब आप खत्म करिये क्योंकि ये बाते बिल मे नही है।

11.00 बजे

सेठ लक्ष्मन दास बजाजः स्पीकर साहब, मै थोडे से सुझाव दे रहा हूं अगर इन पर विचार हो जाए तो आसानी हो जाएगी। फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर खरीदने का जो काम है यदि उकसी पावर डी0सी0 साहब को दे दी जाए तो हमारा काम आसानी से हल हो जाएगा। इसके साथ साथ मै यह भी कहना चाहूगा कि जो लोग 30–35 साल मे म्यूनिसिपल कमेटीज की जमीनो पर कब्जे किए हुए बैठे है उन्हे 100 गज के प्लाट दे दिए जाएं और डी0सी0 को अधिकार दे दिया जाए कि वह उचित रेट लगा कर उन्हे अलाट कर दे।

श्री सीता राम सिंगला (गुडगाव): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मै इस बिल का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हू लेकिन कुछ सुझाव भी देना चाहूगा। अच्छी बात है नगरपालिकाओ की आमदनी बढाने के लिए यह बिल पे ा किया गया है लेकिन वहां पर नगरपालिकाओ की जमीन तहे बाजारी पर दी हुई है, उसे दबा कर बेचने की योजना बनाई जा रही है। जिन लोगो ने नायायज

तौर पर कब्जे कर रखे है, वे यह देख रहे है कि ऐडमिनिस्ट्रे ान या सरकार, पुराने कब्जो की जमीन को उन्हे बेच दे। यह सारा काम योजनाबद्ध तरीका से हो रहा है और भाहरो मे जमीने बि रही है। इस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि किराये की आमदनी बरकरार रहे। जंहा तक नक ाा पास करने की बात का ताल्लुक है जो श्री कैला ा जी ने कही, अनऐप्रूवड कालोनी बहुत ज्यादा है, उनके नक ो पास होने चाहिए। मै हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि आमतौर पर उन कालोनीज मे देहात के आदमी बसते है। वे मजदूर या किसान है जो रोजगार के लिए भाहरो मे आते है और अपनी छोटी सी झोपडी बना लेते है। यह बात ठीक है कि वहा पर नक ो पास नही हो रहे और न ही पानी आदि का प्रबध है जिसके कारण कमेटी की आमदनी भी कम हो रही है। इनके बारे मे सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। एक बात मै और सरकार के नोटिस मे लाना चाहूगा कि जो भाराब म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया मे बिकती है, उसका एक रूपया प्रति बोतल के हिसाब से म्यूनिसिपल कमेटी को मिलता है लेकिन बहुत सी ऐसी नगरपालिकाएं भी है जिनको एक रूपया प्रति बोतल नही मिलता। इसलिए लोकल बौडीज विभाग को प्रयास करना चाहिए कि ऐक्साईड एण्ड टैक्से ान डिपार्टमैट से म्यूनिसिपल कमेटियो को पैसा दिलाया जाये ताकि म्यूनिसिपल कमेटियां का विकास हो सके। अनेक म्यूनिसिपल कमेटियो मे पार्क बने हुए है जहा डैलीबेजिज पर या परमानैट तौर पर सैकडे कर्मचारी काम करते है लेकिन वे कर्मचारी पार्को से काम न करके, अधिकारियों की

कोठियो पर काम करते है। परिणामस्वरूप म्यूनिसिपल कमेटियो के पास जो बगीचे और पार्क है, वे पिछडे हुए है। लोकल बोडीज विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि इनका विकास हो सके।

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हू कि कमेटी हाउस टैक्स पर जो ब्याज की दर निर्धारित कर रही है, यह वैसे तो ठीक है, इसका मै समर्थन करता हूं लेकिन सरकार इस स्थिति को भी स्पश्ट करे दे कि यदि गलत बिल दे दिए जाते है तो ब्याज किस हिसाब से वसूल करेगे ? अगर बिल पर कोई औब्जैक ान करेगा तो क्या उस औब्जैक ान के दौरान भी उस पर ब्याज दर वही लगेगा या नही ? दूसरी बात यह है कि कमेटियों की जीमन पर जंहा नायाजन कब्जे किये हुए है, और कमेटी की तरफ से पानी की व्यवस्था भी नही है, उनके बारे मे जब कमेटी से पूछा जाता है तो कमेटी वाले कह देते है कि पानी की व्यवस्था का टोटल चार्ज पब्लिक हैल्थ विभाग के हाथ मे है। जब पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैट से पूछाा जाता है तो वह कह देता है कि कमेटी के हाथ मे है। इसलिए इन दोनेा विभागो मे तालमेल होनी चाहिए जिससे पानी की व्यवस्था ठीक हो। यही सीवरेज की हालत है। अध्यक्ष महोदय, मै एक बात और भी कहना चाहता हू कि यह ब्याज दर बढाने की बात नही बल्कि कर की चोरी रोकने की बात है। औक्ट्राय की चोरी रूक जाये तो कमेटियों की जो दयानीय आर्थिक स्थिति है

वह सुधर सकती है और प्रदे ा की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है।

स्थानीय भाासन मंत्री श्री सुभाश चन्द कटियालः अध्यक्ष महोदय, भार्मा जी ने अनाधिकृत कालोनियों के बारे मे जो बात रखी है, उसके बारे मे मै यह कहना चाहूगा कि नक ाा पास करने का अधिकार कमेटी को ही है, इसमे कोई भाक वाली बात नही है और कालोनी पास करने का अधिकार टाउन एण्ड कन्ट्री विभाग के पास है ं। हम उनसे विचार विम र्ा कर रहे है और कोि ा ा कर रहे है कि जो लोग भाहरो मे आ रहे है उनके लिए कोई तरीका बनाया जाये ताकि उनके रहन सहन का इतजाम हो सके। भामतलात जमीन के बारे बजाज साहब ने कहा है कि इसे अलौट करने की पावर डी0सी0 को दे दी जाये। इस बारे मे कानून बनाया गया था लेकिन कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है और अब नए सिरे से बात चल रही है कि इस बारे मे क्या किया जाये।

सिंगला साहब ने एक बात कही कि यह बाजारी की जमीन नही बेचनी चाहिये। सरकार की कोई ऐसी पालिसी तो है नही कि तह बाजारी की जमीन बेची जाये और न ही इस बात की कोई मजूरी दी जा रही है। जंहा तक भाराब की इन्कम के बारे मे बात है, उसके बारे मे नियमित रूप से प्रावधान रखा गया है। कि नगरपालिकाओ को इनकी इन्कम पहुचे। कईयों की यह पहुचे चुकी है और कईयो को पहुचने वाली है।

आर्य साहब ने भी पानी के बारे मे एक बात कही। पानी की व्यवस्था को सही बनाने के लिए हम पूरी कोि ा ा करने जा रहे है। नगरपालिकओ को स्वंय आत्मनिर्भर बनाने की दि ाा मे ही यह बिल लाया गया है ताकि नरगपालिकाओ की स्थिति मजबूत हो सके। लगभग 6 करोड रूपये के हाउस टैक्स के बिल पडे हुए है। उनको लेने के लिय यानी उगराही करने के लिये यह सोचा गया है कि कुछ ब्याज लगाया जाये ताकि लोगो के दिमाग मे यह बात हो कि अगर हम बिल की पेमैट लेट भरेगे जो ब्याज देना पडेगा। इन भाब्दो के साथ मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal Amendment Bill be taken into consideration at Once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now the Minister Will move that the Bill be passed.

स्थानीय भाासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the bill be passed

The motion was carried

(ii) **दि हरियाणा अर्बन कट्रोल औफ रैट एण्ड ऐविक ान अमैडमैट बिल, 1990**

Mr. Speaker: Now, the Local Government Minister will untroduce the Haryana Urban Control of Rent and Eviction Amendment Bill. 1990 and also move the motion for its consideration.

स्थानीय भाासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा नगरीय (किराया और बेदखली नियत्रण) सं ाोधन विधेयक, 1990 प्रस्तुत करता हूं।

मै यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा नगररिय किराया और बेदखली नियत्रण) सं ाोधन विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryan Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री हीना नन्द आर्य(लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने हरियाणा नगरीय (किराया और बेदखली नियत्रण) सं ाोधन विधेयक 1990 प्रस्तुत किया है मै उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बिल वि ोश रूप से इस बात के लिये है कि कर्मचारियो को सुविधा दी जाये। हमारी सरकार जब से सत्ता

मे आयी है कर्मचारियो को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सुविधा देती आयी है। कर्मचारियो के पिछले दिनां ही 27 दिन का बोनस दिया गया। इसके अलावा सरकार ने उनके लिए टाईम स्केल देने का भी प्रोवीजन किया है, टाईम बाउन्ड प्रोमो ान देने की व्यवस्था भी की है और कई प्रकार के कदम उठाये है। यह स ाोधान इस बात का भी घोतक है कि कर्मचारियो की सुख सुविधा तथा उनके रहने की व्यवस्था की जाये। अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो जाये या रिटायरमैट से पहले ही उसकी किसी कारणव ा मुत्यु हो जाये, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका मकान खाली हो सके। सर्विस के दौरान तो उसको सरकारी मकान मिलता है। कई कर्मचारियों के पास अपना मकान होता है और वह अपना मकान किराये के लिये दे देते है। अपना मकान खाली करवाने की सुविधा अब तक केवल ऐक्स सर्विसमैन को ही दी गयी थी। लेकिन इस विधेयक द्वारा सरकार यह स ाोधन कर रही है कि अगर कोई कर्मचारी, चाहे वह केन्द्र सरकार की नौकरी करता हो, चाहे प्रान्तीय सरकार की नौकरी करता हो, चाहे किसी बोर्ड अथवा कारपोरे ान की सर्विस करता हो, उसकी रिटायरमैट पर या उसकी मृत्यु होने की सूरत मे उसके बच्चे या उत्तराधिकारी को एक साल के अन्दर अन्दर किरायेदार को बेदखल करके अपने मकान मे रहने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस बिल के द्वारा जो प्रबन्ध किया है, मै इसका स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही मै एक सुझाव भी देना चाहता हू। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए

बहुत काम कियें है और यह भी उसकी का एक अंग है लेकिन कर्मचारियों मे कभी कभार असोतश और गलतफहमी की बात आती रहती है। मेरा सुझाव है कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों के प्रतिनिधियो और सरकार के बीच कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमे दोने बैठकर बातचीत करके समस्या हल कर सके। अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी समिति गठित की जाए जो दो तीन या चार महीने मे बैठक करके समस्या का निदान खोज सके। उस समिति मे प्र ाासक, भाासक और कर्मचारियो के प्रतिनिधि होने चाहिए और उनमे तालमेल बना रहना चाहिए। दो चार महीने मे उस समिति की बैठक हो और बातचीत के द्वारा समस्या हल की जाए जिससे दोनो पक्षो को कोई दिक्कत न हो और आपसी टकराव की स्थिति को टाला जा सके।

श्री हरनाम सिंह (ाहबाद): स्पीकर साहब, मैने इस विधेयक पर एक अमैडमैट दी है। जंहा तक विधेयक का ताल्लुक है, यह एक अच्छा विधेयक है। इससे सेवा निवृत कर्मचारियो को अपने भवन मे जाने मे कोई दिक्कत नही आएगी लेकिन इस विधेयक के दुरूपयोग होने का डर रहेगा। डर यह है कि लोग बेदखली कराने के लिए अपने मकान की अपने किसी रि तेदार, जो कर्मचारी होगा, के नाम कर देगे और इस तरह से आसानी मे मकान खाली हो जाएगा। वाकई मे अगर किसी कर्मचारी का सचमूच मे अपना भवन है और वह उसका दुरूपयोग नही कना चाहता यानी सिर्फ बेदखली के लिए ही वह मकान खाली नही

कराना चाहता तेा ऐसी सूरत मे वह दस साल पहले से मालिक होना चाहिए। अगर वह एक साल पहले ही मकान खरीदता है और बेदखल करने की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि वह केवल किरायेदार को बेदखल करने के लिए ही उस भवन का मालिक बना है। इसलिए मेरा अमैडमैट इसमे भाामिल किया जाए कि दस साल से वह कर्मचारी उस भवन का मालिक हो। इससे यह होगा कि जो कर्मचारी ठीक दस साल पहले ही किसी को बेदखल करने के लिए मकान खरीदा है, वह अपने किराये दार को नही निकाल सकेगा। इसलिए मैने जो अमैडमैट दी हुई है, उसको स्वीकार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, मैने उसको डिसअली कर दिया है।

स्थानीय भाासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, श्री हीरा नन्द आर्य ने कर्मचारियो और सरकार मे तालमेल के बारे मे समिति बनाने सम्बन्धित सुझाव दिया है, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, डा0 हरनाम सिंह ने इसके दुरूपयोग की बात कही है। मै समझता हू कि कोई ऐसी बात नही है, इसलिए इस पर अमैडमैट की कोई जरूरत नही है। एक कर्मचारी के लिए दस साल पहले मकान लेना कई बार मु ि कल होता है। सभी कर्मचारी दस साल पहले मकान नही खरीद सकते। इसलिए मै समझता हू कि इस अमैडमैट की कोई आव यकता नही है।

श्री अध्यक्षः वह मैने डिसअली कर दी है।

श्री सुभाश चन्द कटियालः ठीक है जी।

The motion was carried **Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana Urban (control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at Once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now the Minister Will move that the Bill be passed.

Local Government Minister(Shri Subhash Chand Katyal): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Bill be passed.

(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिंज एण्ड पैन् ान औफ मैम्बर्ज अमैडमैट) बिल, 1990

Mr. Speaker: Now the Home Minister will introduce the Haryan Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1990 and also move the motion for its consideration.

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to intreduce the Haryana Legislative Assemble (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1990.

Sir, I also beg to move-

That the Haryan Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryan Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मै इस बिल के विशय मे यह कहना चाहता हू कि चाहे इस बिल के माध्यम से विधायक या मन्त्री का 100 रूपये बढा दो, चाहे 200 रूपये बढा दो, लेकिन लोगो के दिलो मे आम यह धारण बनी हुई है कि विधायको व मंन्त्रियो की तनख्वाह तो होनी ही नही चाहिये। अगर तनख्वाह दो तो उन्हे इतनी दो ताकि व ईमानदारी रह सके और वह अपना गुजारा ईमानदारी से कर सके। अध्यक्ष महोदय, 1935 मे एक मंत्री का वेतन पांच हजार होता था जिसकी आजकल के वक्त मे अगर वैल्यु लगाई जाए तो 50000 रूपये बनती है। इसी तरह से एम0एल0एज0 की अगर रे ाो लगाए तो उसका वेतन भी अढाई तीन हजार के लगभग होता था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्र ाासन इस बात से बदनाम नही होता कि तनख्वाह

कितनी है बल्कि देखता यह है कि हम ईमानदारी से भाासन व प्र ाासन कितना चला पतो है। यह लूट मार, नाजायज कब्जे, हेराफेरी इसिलिये होती है कि मंत्री और विधायक को उनके खर्चे के हिसाब से, उनकी पोजी ान के हिसाब से वेतन नही मिलता। यह नि चत करवा दिया जाए कि उसका वेतन कम से कम इतना हो जाए ताकि वह ईमानदारी से अपना काम कर सके और बच्चो का गुजारा कर सके। मै कोई हिपोक्रेसी कि बात नही कर रहा। मै तो केवल इतना ही कहना चाहता हू अध्यक्ष महोदय, कि आप स्वय हीइस बात का अन्दाजा लगाईए कि अगर कोई आदमी, विधायक या मंत्री के पास मिलने के लिए आता है तो वह चाय के वक्त चाय मागेगा, खाने के वक्त खाना मागेगा और अगर वह रात को ठहरता है उसको सोने के लिये बिस्तर भी चाहिय। इन सब बातो के खर्चे के मुताबिक अगर कोई विधायक या मंत्री बढौरतरी की बात करता है तो फिर लोग कहेगे, कि जब हमारी तनख्वाह बढाने की बात कही जाती है तो बढाते नही और अपने लिये सब तरह की बढौरती कर रहे है। कर्मचारी लोग भी यही कहेगे कि अपनी तनख्वाह व भते बढा लेते है और हमारी बढाते नही । तो मै यह कहना चाहता हू कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे विधायक या मंत्री लोग ईमानदारी से अपना गुजारा कर सके। बार बार इस तरह की बढौतरी करने की बजाये एक ही बार, दो हजार, चार हजार, दस हजार बढा दे ताकि वह आराम से रहे सके। अगर हमारे पास आने जाने वालों के खर्चे को देखा जाए तो, स्पीकर साहब, आप यह महसूस करेगे कि यह जो बढौतरी की जा रही है,

यह बहुत थोडी है। बेईमान आदमी के लिये तो यह कुछ भी नही है। वह तो बैठ बैठ यूही दो दो हजार रूपया खर्च कर देता है क्यो कि उसने रूपया बेईमानी से कमाया होता है। मैने एक और प्वायट की और भी ध्यान दिलाना है। अगर किसी विधायक या मंत्री की हैसियत अच्छी है तो वह बे ाक इसे न ले, इससे कोई फर्क नही पडता क्योकि कई लोग ऐसे है जो एक रूपया तनख्वाह लेकन भी मंत्री बनने के लिए तैयार है और ऐसे लोग भी है जिनको अगर एम0एल0ए0 बना दे तो वे एक रूपया अपनी जेब से भी देने के लिए तैयार रहते है। ऐसे व्यक्तियों से सरकार, प्र ाासन ठीक प्रकार से नही चल पाता।

इसी तरह से पै ान की बात है। पै ान अगर विधायक की करो तो कम से कम चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा हो, चाहे एक रूपया ही ज्यादा क्यों न हो। हमारा दर्जी उन से कम नही है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। हमे उन से ज्यादा पै ान मिलनी चाहिये, उनकी चाहे घटा दो। सैक्रेटरी या चीफ सैक्रेटरी की जब तनख्वाह बढाने की बात आती है, गुजारे की बात आती है तो कहते है कि उनकी बढौरती कर दो। क्या उनको हमारे से ज्यादा पर लगे है ? मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्र ाासक से भाासन करने वाले ऊपर होते है, इसलिये उनकी तनख्वाह भी उनसे ज्यादा होनी चाहिये, चाहे एक ही रूपया क्यो न हो, वरना हमारी बात ठीक नह बैठती। इसलिये ईमानदारी व्यक्ति अगर ईमानदारी से इस बढे हुए पैसो को लेना चाहे तो ले ले, अगर कोई ने लेना

चाहे तो टाल कर दे। बस मै इतना ही कहना चाहता था। अन्त मे, मै एक बार फिर कहूगा कि इस तरह से विधायको व मन्त्रियो के लिये बार बार बढाने से बेहतर होगा कि एक ही बार बढौतरी कर दी जाए। धन्यवाद।

श्री हरनाम सिंह (ाहबाद): स्पीकर साहब, मै यह अर्ज करना चाहता हू कि हम भारत दे ा के वासी है, हरियाणा के रहने वाले है तथा जनता के प्रतिनिधि है। मै समझता हू कि विधायक और जनता का निकट का संबध होना चाहिए। हमारा जीवन ऊचे आद र्ा का तो होना चाहिए। इसलिए यह जो अलाउंस बढाया है इससे मे सहमत नही हू। लेकिन जो टैलिफोन का अलाउस बढाया है, वह ठीक है क्योकि टैलिफोन की फाल्ज के रेट बढ गए है। तीसरी बात यह है जिस के बारे मे मैने अमैडमैट दी है एक विधायक के लिए बहुत जरूरी है कि वह लोगो का सही रूप से प्रतिनिधित्व कर सके। लोगो की जो दुख तकलीफ और ि ाकायते है, उनको लिख कर सरकार तक भेजना, हमारे लिये बगैर किसी क्लर्क और दफतर से बहुत मु ि कल है। मै चाहता हू कि विधायको के लिए ऐसा प्रवाधान करना चाहिए ताकि हम एक इफैक्टिव विधायक बन सके और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। इसके साथ साथ मै यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली, बिहारख यू0पी0 तथा दूसरे प्रदे ाो के बारे मे मैने सुना है कि विधायको को हर साल अपनी कास्टिचुऐंसी मे डिवैल्पमैट के लिए कुछ रूपया दिया जाता है। यानी अपनी कास्टिचयूऐंसी मे डिवैल्पमैट के लिए,

जो कार्य वह ठीक समझे, उस पैसे को वहां दे दे। मंत्रियो के पास ऐसा होता है। मै समझता हू कि हर एक विधायक के लिए यह रा ि ा नि ि चत होनी चाहिए ताकि वे अपनी अपनी कास्टिचुऐंसी मे डिवैल्पमैट के लिए, अपने तौर पर रूपया खर्च कर सके। इन लफजो के साथ मै इस बिल का स्वागत करता हूं।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, your amendment has been disallowed Question is-

That the Haryan Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub –Clause (2) Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub - clause 2 of clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

Sub –Clause (2) Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub - clause 2 of clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now the Minister Will move that the Bill be passed.

Home Minister(Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Bill be passed.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव–

15.1.1990 तक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण को द र्शाने वाले विवरण सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon'ble Members there is a motion under Rule 84 from Dr. Mangal Sein, M.L.A for the discussion of the stgatement showing the Loans raised by the Haryana State Electricity Board up to 15-1-1990, which was laid on the Table of the House on the 20th March, 1990. He may please move his motion.

(Dr. Mangal Sein was not present in the House)

Mr. Speaker: As the Hon'ble Members is not present, the motion is not moved and discussed.

अब हाउस साइने डाई ऐडजर्न होता है।

11.00 बजे

(तत्प चात सदन नि चत काल के लिए स्थगित हुआ।)